



# विन्ध्य टाइगर



खत्म होगा खेड़की दौला टोल प्लाजा : गडकरी

5

डेविड मिलर ने ले लिया सन्यास? 6

# वित्तमंत्री ने सदन में पेश किया सरकार का बजट

## शिक्षकों के 11 हजार और पुलिस के 7500 पदों पर होगी भर्ती, 6 शहरों में चलेगी 552 ई-बस

**भोपाल।** मध्य प्रदेश विधानसभा में आज डॉ. मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश हुआ। विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट प्रस्तुत किया। इस दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा होने लगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्षी विधायकों से कहा कि आप जिस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, उस पर बाद में बात हो जाएगी। पहले बजट भाषण हो जाए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उठायी सदन में गलत जानकारी देने का मुद्दा। इसके बाद यहाँ हंगामा शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मान्य परंपराओं का पालन करें जो विषय उठया जा चुका है, वह दोबारा नहीं उठया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अब नरिंसंग घोटाला मामले पर कोई चर्चा नहीं होगी।

मंत्री जगदीश देवड़ा ने भाषण पढ़ते हुए कहा कि बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। हम बाधाओं को पर कर विकास करेंगे। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बिजली देने पर काम हो रहा है। ऑकरेश्वर में 100 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। बजट में कृषि को लाभ का क्षेत्र बनाने की योजना है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए राशि दी गई है। 48 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल सहित 6 शहरों में 552 ई-बस चलाई जाएंगी।

**तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये**  
वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद भविष्य निधि तुरंत मिलेगी। इसके साथ ही 50 करोड़ रुपये तीर्थ दर्शन योजना के लिए दिए जाएंगे। 4725 करोड़ रुपये का प्रावधान वन और पर्यावरण के लिए किया गया है।

वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा- आगामी 5 साल में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से अटल प्रगति पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विन्ध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निर्माण एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड विकास पथ और मध्य भारत विकास पथ के कार्य किए जाएंगे। इन मागों के दोनों और औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाएंगे।

**सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में बनेंगी सड़कें**  
सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन शहर में बाइपास तथा शहर में सभी

मागों को फोरलेन और 8 लेन की सड़क प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2000 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क एवं पुल के निर्माण व संधारण के लिए बजट 10000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश में अभी तक 70 लाख 860293 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को औसतान प्रतिदिन 10 घंटे विद्युत प्रदाय की जाएगी। प्रदेश में 26 जनवरी 2024 को सर्वाधिक 17614 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की गई। वर्ष 2024-25 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 19406 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो 2023-24 की तुलना में 1046 करोड़ रुपये अधिक है। हंगामे के बीच वित्तमंत्री बजट भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं।

इसके पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के भाषण अनुमोदन हुआ। इसके बाद कैबिनेट में बजट को मंजूरी दी गई।

**पार्वती, काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना**  
2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर और 2028-29 तक एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को संचित करने का लक्ष्य रखा गया है। पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी लिंक परियोजना निर्माण की सैद्धांतिक सहमति बनाई गई है। इससे प्रदेश के 10 जिलों में चार लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी और पेयजल मिलेगा सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। केन-बेतवा लिंक परियोजना और के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

**कोटी कुटकी पर 10 रुपये प्रति किलो की अतिरिक्त राशि**  
राज्य मिले मिशन मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया है। कोटी कुटकी पर प्रति किलोग्राम 10 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। डिंडौरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी। अनुसूचित जाति जनजाति के एक हेक्टेयर तक के भूमि धारकों को



बजट में सरकार ने जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया

5 हॉर्स पावर तक के विद्युत पंप पर निशुल्क विद्युत आपूर्ति। अटल कृषि ज्योति योजना अंतर्गत 10 हॉर्स पावर तक के किसानों को ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए 11065 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।

**मुख्यमंत्री कृषि कल्याण योजना** में 4900 करोड़ रुपए रखे गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजना से 42 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गेहूं पर 125 रुपए प्रति कुंतल बोनस देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

**किसानों को लोन के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान**  
प्राकृतिक आपदा से होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए 2000 करोड़ रुपए रखे गए हैं फसल विविधीकरण योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 0ल पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।

**प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 30 करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री उज्जला योजना में शामिल होने से वंचित हितग्राहियों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार की योजना के लिए 520 करोड़ रुपए रखे गए हैं। किसानों को 23 हजार करोड़ रुपए के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है।**

गौशालाओं में पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रतिदिन अब 20 के स्थान पर 40 रुपये व्यय किए जाएंगे। वर्ष 2024-25 को गो वंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा

**2 साल में आठ और मेडिकल कॉलेज खोलने का होगा प्रयास**  
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 40000 पद निर्मित किए गए हैं। वर्ष 2024-25 में मंदसौर नीमच और सिवनी में मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे। इसके बाद आगामी 2 वर्षों में 8 और मेडिकल कॉलेज संचालित करने का सरकार प्रयास करेगी।

**कॉलेज के संचालन से स्नातक स्तर पर 3605 और स्नातकोत्तर स्तर पर 1560 सीटों की वृद्धि होगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चार करोड़ एक लाख सदस्यों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस योजना के लिए 1381 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 45ल अधिक है।**

**गंधीर रोगियों को मिलेगा उपचार**  
गंधीर रोगियों को आपात स्थिति में उपचार उपलब्ध कराने के लिए पीएम श्री एयर एंजुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। वहीं मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा की शुरुआत भी की गई है। 800 आयुष आरोग्य मॉडर का संचालन भी प्रारंभ किया गया है। बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेद कॉलेज प्रारंभ किए जाएंगे। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 21 हजार 444 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले साल की तुलना में 34ल अधिक है।

**सीएम राइस स्कूलों में परिवहन व्यवस्था**  
वर्ष 2024-25 में 150 सीएम राइस स्कूल नवीन भवन में संचालित होंगे। इन विद्यालयों में एक किलोमीटर से अधिक दूर रहे बच्चों के लिए परिवहन व्यवस्था लागू की गई है। सीएम राइस विद्यालयों के

लिए 2737 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वर्ष 2024-25 में 3200 प्राथमिक शालाओं में पूर्व प्राथमिक शालाएं प्रारंभ की जाएंगी। 11000 शिक्षकों की नियुक्तियां की जा रही हैं। पीएम श्री योजना अंतर्गत 22 नवीन छात्रावास प्रारंभ किए जाएंगे। 87 लाख विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ पुस्तक और गणेश दिए जाएंगे।

**पीएम कॉलेज ऑफ एक्ससीलेंस बनेंगे**  
पीएम उषा परियोजना के लिए 565 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। प्रत्येक जिले में पूर्व से संचालित एक महाविद्यालय को पीएम कॉलेज ऑफ एक्ससीलेंस के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। इन महाविद्यालय के लिए 2000 से अधिक नए पद रचित किए गए हैं। 247 महाविद्यालयों के लिए 244 करोड़ रुपए का प्रावधान कर भीतिक एवं अकादमी का अधोसंरचना विकास के कार्य कराए जाएंगे।

**लाइली बहना योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया**  
प्रत्येक संभाग स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कोडिंग लैब की स्थापना की जाएगी। लाइली बहना योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। लाइली लक्ष्मी योजना में 48 लाख 3000 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। 11706 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नत किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री जन मन महा अभियान के अंतर्गत 217 आंगनवाड़ी भवनों के लिए फिर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 26560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह गत वर्ष से 81ल अधिक है

महिलाओं एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सभी विभागों में योजनाएं संचालित हैं। जेंडर बजट 2024-25 का 1,21,997 करोड़ रुपए है। शिक्षा क्षेत्र के लिए 52682 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

**खेल और युवा कल्याण के लिए 586 करोड़ का प्रावधान**  
मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाने के लिए नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण व अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। शासकीय सेवा में नियुक्ति की चयन परीक्षा के लिए युवाओं द्वारा जमा किए जाने वाले आवेदन शुल्क का भार काम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई नीति बनाई जाएगी। खेल एवं युवा कल्याण के लिए 586 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विकास के सरकार कटिबद्ध है।

**जनमन योजना के लिए 1607 करोड़ रुपये का प्रावधान**  
प्रधानमंत्री जन मन योजना के लिए 1607 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 94 सीएम राइज स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। 2024-25 में 38 विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर शैक्षणिक व्यवस्थाएं प्रारंभ की जाएगी।

2024-25 में सीएम राइज विद्यालयों के लिए 667 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। वेगा, भारिया, सहरिया जाति के लोगों को निशुल्क आहार उपलब्ध कराने के लिए 450 करोड़ रुपए का आहार अनुदान दिया जाए।

अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए 27900 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, गणवेश और छात्रावास सुविधा आदि के लिए 1427 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 1704 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

सामाजिक न्याय के अंतर्गत पेंशन एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए 4421 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना अभिभावक पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं शामिल हैं। प्रदेश में हो रहा औद्योगिक विकास

वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए सरकार निरंतर कदम उठा रही है। राज्य ने ऑटोमोबाइल, वस्त्र, पर्यटन, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास, फॉर्मो, अक्षय ऊर्जा, वेयरहाउसिंग को ऐसे ट्रस्ट सेक्टर के रूप में चिह्नित किया है। यह आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करते हैं। उज्जैन में प्रथम रोजनल इंडस्ट्री में लगभग 12170 करोड़ रुपए का निवेश और 26000 से अधिक नवीन रोजगार उपलब्ध होना संभावित है। विभिन्न जिलों में 10 हजार 64 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाले 61 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण भूमि पूजन किया गया है।

**जनवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का होगा आयोजन**  
जनवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजन होगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को और प्रभावी बनाया जाएगा। उद्योग क्षेत्र के लिए 4190 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 27870 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। हर साल जल गंगा संवर्धन अभियान जैसी गतिविधियां संचालित की जाएगी।

स्वच्छ भारत मिशन योजना के लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मध्यम भोजन 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। रसोइयों का मानदेय 400 रुपये प्रति माह से बढ़कर 3400 किया गया है। मनरेगा के लिए 3500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1800 और इन सड़कों के नवीनीकरण के लिए 900 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया।

**नगरीय विकास के लिए 16744 करोड़ रुपए का प्रावधान किया**  
नगरीय क्षेत्रों में जन भागीदारी के माध्यम से दो संरचना विकास के लिए मुख्यमंत्री जन सहभागिता निर्माण योजना तथा प्रदेश के शहरी क्षेत्र में नागरिकों के स्वास्थ्य जीवन यापन के लिए नगर वनीकरण योजना लागू की जाएगी। 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ मेला आयोजित होगा। इसके लिए 10 जिलों में आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के

लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उज्जैन तथा जबलपुर शहर को आगामी तीन वर्ष में केंद्र सरकार से 270 करोड़ रुपए मिलेंगे।

**प्रदेश के 6 शहरों में चलेगी 552 ई-बसें**  
शहरों के मास्टर प्लान की सड़कों के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कायाकल्प योजना के लिए नगरीय क्षेत्र में आदर्श संरचना निर्माण योजना के लिए 1100 करोड़, मुख्यमंत्री अधो संरचना विकास योजना के अंतर्गत 1700 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य चल रहे हैं। प्रधानमंत्री की बस योजना अंतर्गत इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में 552 बसों का संचालन किया जाएगा।

शासकीय सेवकों के सातवें वेतनमान के परिपेक्ष में पुनरीक्षण के लिए समिति का प्रतिवेदन मिल गया है। इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य नीति के अंतिम धुतान प्राधिकार पत्र जारी करने की ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की जा रही है। बजट में किसी तरह का कोई नया कर अधिरोपित नहीं करने वह कर नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव है।

**भोपाल और इंदौर में जल्द शुरू होगी मेट्रो**  
भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल का संचालन शीघ्र प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सभी निकायों को सम्मिलित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी शहरों में टोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं जल प्रबंधन के लिए आगामी 5 वर्ष में 5000 करोड़ रुपए का निवेश होगा।

**श्रीकृष्ण पाथेय योजना लागू होगी**  
वीर भारत न्यास स्थापित किया जा रहा है। भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों से पथगमन किया था। इन्हें चिह्नित कर विकसित किया जाएगा, श्री कृष्ण पाथेय योजना लागू होगी।

विधायकों को ई-ऑफिस योजना अंतर्गत प्रति विधायक 500000 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। ई-विधान, ई-कैबिनेट, ई-विधायक ऑफिस बनाने की कार्य योजना का क्रियान्वयन जल्द किया जाएगा। सहकारी संस्थाओं के कंप्यूटीकरण के लिए 32 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वन एवं पर्यावरण के लिए 4725 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।

## पेपर लीक के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं: पीएम

राज्यसभा में पीएम मोदी की स्पीच, विपक्ष का वॉकआउट

**नई दिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। 1 घंटा 50 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री नीत, मणिपुर संविधान, कांग्रेस, पश्चिम बंगाल, रोजगार, भ्रष्टाचार, सीबीआई-ईडी, फेडरलिज्म, इमरजेंसी, जम्मू-कश्मीर, इंदिरा, राहुल, दलितों पर बोले।

प्रधानमंत्री मोदी जब 32 मिनट बोल चुके थे, तब विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट किया। वॉकआउट प्रधानमंत्री द्वारा सोनिया गांधी पर निशाना साधने के बाद हुआ। उन्होंने कहा- ये लोग ऐसे हैं, जो ऑटो पायलट और रिमोट पायलट पर सरकार चलाने के आदी हैं। वे काम करने में विश्वास नहीं रखते, वे बस इंतजार



भी इन्होंने राजनीति की भेंट चढ़ा दी। मैं देश के नौजवानों को आश्चस्त करता हूँ कि आपको धोखा देने वालों को यह सरकार छोड़ने वाली नहीं है। इन्हें सख्त सजा मिले, इसलिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। हमने इसके लिए सख्त कानून बनाया है।

2. मणिपुर हिंसा पर मणिपुर में लगातार हिंसक घटनाएं कम हो रही हैं। स्कूल-कॉलेज, दफतर और अन्य संस्थान चल रहे हैं। मणिपुर में भी परीक्षाएं हुई हैं। जो भी तत्व मणिपुर की आग में धो डाल रहे हैं, एक समय आएगा जब मणिपुर उन्हें रिजेक्ट कर देगा।

जो लोग मणिपुर का इतिहास जानते हैं, उन्हें पता है कि वहां सामाजिक संघर्ष का इतिहास रहा है।

## बजट में युवा, गरीब, महिला, किसान सहित सभी वर्गों का रखा गया है ध्यान : डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2024-25 के बजट को सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार 03 लाख 60 हजार करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट की यह विशेषता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। किसी भी विभाग की अपेक्षित राशि को कम नहीं किया गया, अपितु सभी विभागों के आवंटन में वृद्धि की गई है। विकसित भारत-विकसित मध्यप्रदेश'' की थीम पर प्रस्तुत बजट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षा अनुसार जीडीपी की ग्रोथ को सुनिश्चित करते हुए आगामी पाँच वर्षों में बजट का आकार दोगुना किया जाएगा।

## झारखंड सीएम चंपई सोरेन ने दिया इस्तीफा

हेमंत सोरेन चुने गए विधायक दल के नेता, मुख्यमंत्री बनना तय

**रांची।** झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। चंपई सोरेन ने पहले ही राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा था। राज्य की राजनीति में हलचल की सुगबुगाहट आज दोपहर से ही तेज हो गई थी। अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के इस्तीफे के साथ ही यह तय हो गया है कि हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) गठबंधन के विधायक दल के नेता होंगे। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद चंपई सोरेन ने कहा, 'बैठक में हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है। इसे लेकर सभी विधायकों ने सहमति जताई है। जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ था, तो मुझे चुना गया। राजनीतिक घटनाक्रम क्या है, ये आप सब



जानते हैं। हमारे गठबंधन में हम सभी ने फिर से निर्णय लिया है कि हेमंत सोरेन हमारे नेता होंगे। मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हमने अपने गठबंधन के निर्णय के अनुसार काम किया है।' आपको बता दें कि दो फरवरी को चंपई सोरेन ने झारखंड के बारहवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले चंपई सोरेन के आवास

महीने बाद जेल से रिहा किया गया था। जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में अदालत से जमानत मिलने बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया। हेमंत ने 31 जनवरी को गिरफ्तार होने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उधर, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने चंपई सोरेन के इस्तीफे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा 'झामुमो और कांग्रेस द्वारा झारखंड में एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री पद से हटाना बेहद दुःख है। मुझे यकीन है कि झारखंड के लोग इस कार्रवाई का विरोध करेंगे।' उधर भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकान्त दुबे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, 'झारखंड में चंपई सोरेन युग समाप्त हो रहा है।

## सहायक संचालक और डीईओ के भ्रमण में एक स्कूल बंद, 8 शिक्षक ड्यूटी से मिले गायब

काम में लापरवाह शिक्षक की दो वेतन वृद्धि रोकी, 250 में 18 छात्रों की रही उपस्थिति

**सिंगरौली।** सरखी के बावजूद ग्रामीण अंचलों में संचालित स्कूलों के शिक्षकों की आदतों में सुधार नहीं हो रहा है। शिक्षक मनमानी तरीके से स्कूल में देर से आना और बिना बताए हस्ताक्षर कर गायब हो जाना अब दैनिक दिनचर्या बन चुकी है। इस बात का खुलासा सहायक संचालक सुश्री कविता त्रिपाठी और जिला शिक्षा अधिकारी एसबी सिंह के निरीक्षण के दौरान हुआ है। अलग-अलग कई विद्यालयों में निरीक्षण किया गया जहां प्राथमिक विद्यालय बगहिया परसोहर विद्यालय बंद पाई गई। जबकि अन्य विद्यालयों के 8 शिक्षक ड्यूटी से गायब मिले। वहीं एक शिक्षक हस्ताक्षर बनाकर ड्यूटी से गायब रहे। साथ ही हाई स्कूल कुंदवार स्कूल में बच्चों की उपस्थिति भी बेहद कम रही।

मिली जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी सुबह 10:30 बजे निरीक्षण के लिए शा.उ. मा. वि. करदा पहुंचे। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में प्राथमिक प्रारंभ थी। प्राथमिक में जिला शिक्षा अधिकारी सम्मिलित हुए। संस्था में कुल 11 शिक्षक कार्यरत हैं जिसमें से 2 शिक्षक एवं दो लिपिक व 1 भूय अनुपस्थिति पाए गए। वहीं माध्यमिक विद्यालय कोडरिया संकुल सरौधा में एक शिक्षक अनुपस्थित, हाई स्कूल कुंदवार में दो शिक्षक अनुपस्थित, माध्यमिक विद्यालय भैसाहुड़ संकुल सरौधा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक राजकुमार यादव हस्ताक्षर कर बिना किसी अनुमति के विद्यालय से अनुपस्थित पाए गए। जबकि प्राथमिक विद्यालय बगहिया परसोहर विद्यालय बंद पाई गई। वहीं जन शिक्षा केंद्र सरौधा अंतर्गत जन शिक्षक सुरेश प्रजापति द्वारा अपने पदीय दायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं करने पर 2 वेतन वृद्धि बंद करने कारण बताओं नोटिस दिया गया है। वहीं संकुल केंद्र सरौधा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के निरीक्षण दौरान सभी



शिक्षक उपस्थित पाए गए साथ ही स्मार्ट क्लास सहित सभी कक्षाएं व्यवस्थित संचालित पाई गईं। जहां जिला शिक्षा अधिकारी ने अनुपस्थित शिक्षकों को नोटिस जारी करने के साथ ही प्रधानाध्यापकों को बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का निर्देश दिया। माध्यमिक विद्यालय भैसाहुड़ संकुल सरौधा विद्यालय भले संचालित मिली। लेकिन यहां बच्चों की उपस्थिति 10ख से भी कम रही। विद्यालय में 180 छात्र

शिक्षक, दशरथ सोनार्टी प्राथमिक शिक्षक, लाल जी तिवारी सहायक ग्रेड 2, अमर प्रकाश सिंह सहायक ग्रेड- 3, राघवेंद्र सिंह भुल्य, माध्यमिक विद्यालय कोडरिया संकुल सरौधा के मानसिंह, हाई स्कूल कुंदवार के प्राथमिक शिक्षक नीरज अग्रहरि, वीरेंद्र कुमार रोजिया, माध्यमिक विद्यालय भैसाहुड़ संकुल सरौधा के प्राथमिक शिक्षक राजकुमार यादव हस्ताक्षर कर बिना किसी अनुमति के विद्यालय से अनुपस्थित पाए गए। जबकि जन शिक्षा केंद्र सरौधा अंतर्गत जन शिक्षक सुरेश प्रजापति अपने पदीय दायित्व का निर्वहन सही ढंग से न करने पर 2 वेतन वृद्धि बंद करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

**सहायक संचालक शिक्षा का भ्रमण**  
3 जुलाई को सहायक संचालक शिक्षा सुश्री कविता त्रिपाठी, आर डी साकेत, योजना अधिकारी अशोक शुक्ला ने

शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय परसोना एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गडेरिया का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय संचालित पाई गई। प्राचार्य आकस्मिक अवकाश पर पाए गए संस्था के दो शिक्षक सुश्री सुपमा सिंह प्राथमिक शिक्षक के कर्मचारी उपस्थिति पंजी में सीएल अंकित है लेकिन सक्षम अधिकारी से स्वीकृति नहीं दी गई थी वहीं श्रीमती गीता शुक्ला प्राथमिक शिक्षक के कॉलम में 21 जून 2024 से 3 जुलाई 2024 तक आकस्मिक अवकाश अंकित किया गया है लेकिन सक्षम अधिकारी से स्वीकृति नहीं की गई जो की अनाधिकृत अनुपस्थिति की श्रेणी में आते हैं। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय परसोना में विद्यालय संचालित पाई गई शिक्षकों द्वारा नवाचार होना पाया गया। अनाधिकृत अनुपस्थित शिक्षकों को कारण बताओं पत्र जारी किया गया।

## यातायात नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को फूल-माला देकर किया गया सम्मानित



**सिंगरौली।** श्रीमती निवेदिता गुप्ता (भापुसे) पुलिस अधीक्षक सिंगरौली के निर्देशन में एच शिव कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिंगरौली, एवं पी.एस. परस्ते, नगर पुलिस अधीक्षक विन्ध्यनगर के मार्गदर्शन में जगह-जगह जागरूकता एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों की जागरूकता हेतु लगातार यातायात प्रवर्तन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तारतम्य में आज दिनांक 03-07-2024 को यातायात पुलिस टीम द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों / तिराहों पर यातायात नियमों के संबंध में जानकारी प्रदाय की गई एवं आने-जाने वाले समस्त आमजन जो यातायात नियमों का पालन करते हुए पाये गए उनको फूल-माला देकर सम्मानित किया गया, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने एवं पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाने हेतु बताया गया, चार पहिया वाहनों में सीटबेल्ट लगाने हेतु बताया गया, वाहनों को निर्धारित गतिसीमा से अधिक न चलायें, शराब पीकर वाहन न चलायें। सराहनीय भूमिका उनि अभिषेक पाण्डेय, सडिन सुरेश शुक्ला, हॉमिद खान, शिवेन्द्र सिंह, प्रआर पुष्पेन्द्र, उमेश बागरी, नंदकिशोर, आर. प्रवेश तिवारी एवं अन्य समस्त यातायात स्टाफ योगदान रहा।

## शासकीय भूमि का कूटरचित पट्टा तैयार करने के आरोप में कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज करने के दिये निर्देश

**सिंगरौली।** न्यायालय कलेक्टर जिला सिंगरौली के द्वारा कूट रचित पट्टा तैयार करने के आरोप में संबंधितों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं। विदित हो कि कि संत काछी पिता शीतलाधारी काछी निवासी ग्राम झलरी तहसील सरई के द्वारा शासकीय भूमि ग्राम झलरी के आराजी खसरा नम्बर 117 रकबा 4.13 एकड़ का व्यवस्थापन पट्टा से संबंधित प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा प्रकरण का विधिवत अवलोकन एवं सुनवाई के पश्चात इस आरोप के आदेश पारित किये गये हैं कि आवेदक द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यांकित पट्टा कूटरचित तैयार कराया गया है। साथ ही आवेदक संतन पिता शीतलाधारी काछी एवं पट्टे में उल्लेखित दूसरे व्यक्ति मटुकलाल पिता बबई तेली को दुरभिसिंथ से कूट रचना के

तहत तैयार किया गया है। यह कृत् शासकीय भूमि पर अपना स्वत्व स्थापित करने के आशय से किया गया है। एवं कूट रचना एवं न्यायालय के साथ धोखाधड़ी का कृत् है जो भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत दण्डनीय अपराध है। आवेदक वा उक्त कृत् में सम्मिलित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थिति कराते हुये कार्यवाही किया जाना प्रसंगिक है न्यायालय के सम्पूर्ण विवेचना एवं निष्कर्ष के अवलोकन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को न्यायालय द्वारा अस्वीकार्य करते हुये तहसीलदार सरई को आदेशित किया गया है कि आवेदक संतन पिता शीतलाधारी काछी एवं पट्टे में उल्लेखित दूसरे व्यक्ति मटुकलाल पिता बबई तेली को दुरभिसिंथ से कूट रचना के

## जन्म मृत्यु पंजीयन को लेकर प्रशिक्षण हुआ

**सिंगरौली।** भारत के महा रजिस्टर नई दिल्ली द्वारा जन्म मृत्यु पंजीयन कार्य से संबंधित नवीन प्रारंभ के संबंध में आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए एक दिवसीय प्रशिक्षण कलेक्टर सभागार में दिया गया। सहायक संचालक जनगणना कार्य निदेशालय भोपाल आशीष श्रीवास्तव के द्वारा सहायक संख्यकी अधिकारी जे.एल पनिका के उपस्थिति में जिले में पंजीयन करता इकाइयों नगरी निकाय, चिकित्सालय, एवं समस्त जनपद पंचायत से आएं अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण में जन्म मृत्यु पंजीयन कार्य में आ रही तकनीकी समस्या के निराकरण में कार्य संपादन में सुगमता होगी।

## शारी का झांसा देकर 2 वर्ष तक युवती से करता रहा दुष्कर्म रिपोर्ट के बाद जयंत पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

**सिंगरौली।** लंघाडोल निवासी एक युवक 2 वर्षों तक शारी का झांसा देकर नवानगर की युवती से दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता उसे रोज गार्डन जयंत में मिली थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक ने उसे अपने प्रेम जाल में फसाकर वर्षों तक उससे दुष्कर्म करता रहा। हालांकि अब पीड़िता को तहरीर पर जयंत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी अनुसार माजनकला नवानगर निवासी पीड़िता ने जयंत पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 02 वर्ष पहले 8 मार्च की शाम वह भूमने हेतु रोज गार्डन जयंत गई थी, जहां पबली बार उसकी मुलाकात अभिषेक शाह पिता रमाशंकर शाह निवासी



बिन्दुल थाना लंघाडोल से हुई थी। उसके बाद वह अभिषेक शाह से उसके मोबाइल पर बात करने लगी। आरोपी अभिषेक उससे शारी करने के लिये बोल रहा था वह भी अभिषेक से शारी करना चाहती थी। उसी माह 15 मार्च को

भी युवती से दुष्कर्म किया पर इस बार शारी के बात से मुकर गया और बताते पर जान से मारने की धमकी दी। उरी सहमी युवती ने हिम्मत कर अपनी माँ को पूरी बात बताई जिसके बाद माँ उसे लेकर जयंत चौकी जा पहुँची। जयंत चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सुरेंद्र यादव ने पीड़िता की तहरीर पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता गुप्ता के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के मार्गदर्शन, नगर पुलिस अधीक्षक पीएस परस्ते की सतत निगरानी एवं थाना प्रभारी विन्ध्यनगर अर्चना द्विवेदी के नेतृत्व में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 422/24 धारा 376, 376(2)(द), 506 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण एवं धारा 164 जा0फौ0 कथन कराया गया एवं आरोपी को पता तलास जारी रही। जिसे मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के संबंध में पूछताछ में आरोपी अभिषेक ने अपना जुर्म काबुल लिया। आरोपी को ज्यूडीशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी जयंत सुरेंद्र यादव के साथ सडिन-श्याम विहारी द्विवेदी, प्रआर सुनील मिश्रा, विष्णु रावत, सतीष मिश्रा, कुनाल सिंह, आर सुरेंद्र यादव, गुड्डू सिंह तथा सी0 कुन्जबिहारी सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

## जनसुनवाई की शिकायत का पुलिस अधीक्षक द्वारा कराया गया त्वरित निराकरण

**सिंगरौली।** पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता गुप्ता सिंगरौली द्वारा प्रति मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की जाती है। जिसमें आवेदक चन्द्रिका प्रसाद पनिका पिता स्व. कुबेर लाल पनिका ग्राम करौटी चौकी गोभा थाना बैदन का कल दिनांक 02-07-2024 को पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत पत्र किया था की आवेदक की भूमि अराजी नंबर



26/1 पर गांव के ही रामसेवक बैस तथा उनके परिवार के लोगो द्वारा जबर्न माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के स्थान आदेश को अवहेलना कर रास्ता बंद कर दिया गया है। जो पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा चौकी प्रभारी को गोभा को आवेदक की समस्या का त्वरित निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 03-07-2024

## मकरी मे एक पेड़ माँ के नाम के तहत हुआ पौधरोपण

**सिंगरौली।** प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार बुधवार को सिंगरौली जिले के बरगवा रेंज अंतर्गत मकरी बोट में माँ के नाम एक पेड़ का पौधरोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिसके मुख्य अतिथि भाजपा अध्यक्ष गजेंद्र अग्रहरि रहे, जिसमें अध्यक्ष के द्वारा गया कि कहते हैं सब वेद पुराण बिना वृक्ष के नहीं कल्याण के उद्घोष से शुरुआत करते हुए बोले की पौधे मानव जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है

जितना अपना स्वयं की ज़िंदगी। वृक्ष का सुरक्षा में हमारा उतना ही योगदान होना चाहिए जितना बिश्नोई समाज के अमृतदेवी जी। जिसमे मुख्यरूप से भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष इंजी.रामप्रसाद वर्मा, अरविंद कुमार जी, देवेन्द्र जी एवं वन विभाग स्टाफ के रूप में श सागर शुक्ला रेंजर बरगवा, डिप्टी रेंजर शैलेंद्र मिश्रा, बीट गार्ड हरिशंकर, वन विभाग के स्टाफ एवं उपस्थित रहे।

## निर्माणाधीन भवन पीजी कालेज एवं सीएम राईज विद्यालय का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

**सिंगरौली।** कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा निर्माणाधीन भवन पीजी कालेज गनियारी एवं सीएम राईज विद्यालय हिरवाह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित अधिकांरियों एवं विभागाकारों को इस आशय के निर्देश दिये गये कि भवन निर्माण का कार्य

गुणवत्ता एवं समय सीमा के साथ पूर्ण किया जाये। वहीं मौके पर उपस्थित पीजी कालेज के प्राचार्य एमयू सिद्दीकी एवं कार्यपालन यंत्री पीआईयू प्रदीप चड्ढा के द्वारा निर्माणाधीन भवनों के संबंध में कलेक्टर को निर्माण के प्रगति जानकारी टीएल बैठक के दौरान भी दिये जाने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर एवं उपस्थित अधिकांरियों के द्वारा सीएम राईज विद्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण कर मौके पर उपस्थित अधिकांरियों को रोपण किये गये वृक्ष की देखभाल करने के निर्देश दिये गये। साथ ही विद्यालयों के निर्माण के प्रगति जानकारी टीएल बैठक के दौरान भी दिये जाने के निर्देश दिये गये।

## एनटीपीसी आवासीय परिसर में सेवानिवृत्त कर्मों का बेजा कब्जा

कालोनी के इंटक कार्यालय को बनाया आशियाना, एजीएम एच आर का गोल मोल जवाब

**सिंगरौली।** एनटीपीसी विन्ध्यनगर के आवासीय परिसर स्थित इंटक कार्यालय मे एनटीपीसी से सेवानिवृत्त वीवा क्लब के पूर्व महासचिव व वर्तमान वार्ड नंबर 35 के पार्श्व पति द्वारा निरम कानून को बालाये ताक पर रख अवैध कब्जा जमा लिया गया है। चर्चित महासचिव के कार्यगुजारियों से वाकिफ एनटीपीसी के जिम्मेदार अनजान बने हुए हैं तो दूसरी तरह अन्य सेवानिवृत्त एनटीपीसी कर्मियों के बीच प्रबंधन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं आम है जानकारी के अनुसार एन टी पी सी विन्ध्यनगर से सेवानिवृत्त आर पी पटेल जो वीवा क्लब के पूर्व महासचिव के

साथ वार्ड 35 जो एन टी पी सी आवासीय परिसर मे स्थित है के पार्श्व पति हैं, के द्वारा कालोनी परिसर मे स्थित इंटक कार्यालय पर अवैध रूप से कब्जा जमा कर परियोजना के तमाम नियम कानून को टेगा दिखाया जा रहा है. चर्चित वीवा क्लब पूर्व महासचिव के अवैध कब्जे पर आवासीय परिसर मे ही मौजूद वार्ड 34 के कांग्रेस पार्श्व प्रबंधन की व्यवस्था पर सवाल उठाया है. कांग्रेस पार्श्व का दवे जुवान आरोप है कि जब भी ब्रजेपी पार्श्व पति को एन टी पी सी कालोनी मे रहने कि अनुमति मिल सकती है तो फिर कांग्रेस पार्श्व को क्यों नही आवास दिया जा रहा है. इंटक कार्यालय मे

अवैध कब्जा जमाने का विरोध यही नही थमा बल्कि परियोजना से सेवानिवृत्त दूसरे कर्मों भी विरोध करने लगे हैं और कह रहे हैं कि जब सेवानिवृत्त आर पी पटेल को परियोजना परिसर मे रहने कि अनुमति है तो फिर हम लोगों को भी रहने कि व्यवस्था मुहैया कराई जाय. कालोनी के इंटक कार्यालय मे निवासरत पूर्व महासचिव वीवा क्लब के सवाल पर एजीएम एच आर राकेश अरोरा ने गोल मोल जवाब दिया. उन्होंने डिटेल मे कुछ भी बताते से इंकार किया और कहा कि उन्हें इस बारे मे कोई जानकारी नही है. उक्त अवैध कब्जे पर एन टी पी सी प्रबंधन का ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

## मोरवा विस्थापन एवं पुनर्वास को लेकर दोनों मंचों ने एनसीएल प्रबंधन के साथ की बैठक

पुनर्स्थापना मंच की प्रबंधन के साथ रही बेनतीजा, नापी को लेकर लोगों ने जताया रोष

**सिंगरौली।** सिंगरौली पुनर्स्थापना मंच को एनसीएल प्रबंधन के साथ हुई बैठक में प्रबंधन का रुख स्पष्ट नहीं होने से लोगों में मायूसी दिखाई दे रही है। भूमि व भवन के मूल्यांकन हेतु गणना पत्रक मे एनसीएल प्रबंधन इसी जिले मे रेलवे व राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि अधिग्रहण मे जो नियम लार एक्ट के तहत रेलवे व स्थानीय शासन प्रशासन लागू करते हैं, एनसीएल प्रबंधन वह ना मानते हुए अपने पुराने नियमों को लागू किये जाने की मंशा रखता है व अपना स्पष्ट रुख नहीं रख रहा है। आर एन्ड आर एक्ट के तहत शहर का पुनर्स्थापन स्थल कैंहा होगा उसकी स्थिति भी अभी अस्पष्ट है। विस्थापित व विस्थापन प्रभावित कीन्हे माना जायेगा, इसके बारे मे भी प्रबंधन के लोगो

के मध्य स्पष्ट जानकारी का अभाव है, जिससे की बड़ी संख्या मे यहां पर अनेको संस्थाओ मे कार्यरत लोग, जो की किराये के मकान मे रहते हैं, उनके बारे मे एनसीएल क्या करेगा, इसकी स्थिति भी अस्पष्ट है। पुनर्स्थापन स्थल पर प्लाट ना लेने की स्थिति मे, प्लाट के बदले आज पुनः 1,37,000 रु देने की बात कहना मंच के सदस्यों को स्वीकार नहीं है। सिंगरौली के उद्योगियों को उनके उद्योग को पुनः स्थापित करने मे क्या सहयोग मिलेगा, भूमि कैंहा मिल सकेगी, अभी इसकी कोई रूपरेखा एनसीएल ने तैयार नहीं की है। जमीन के मूल्यांकन हेतु वार्ड 10 जो की अब अस्तित्व मे ही नहीं है उसका 10 साल पुराना रेट सभी वार्डों के मूल्यांकन हेतु देना चाहती है, जबकि पुनर्स्थापन

मंच सिंगरौली नगर निगम के वर्तमान वर्ष 2024 के अधिकतम मूल्य की तीन रजिस्ट्री का औसत के आधार पर भूमि का मूल्यांकन चाहती है। एनसीएल अपना रुख स्पष्ट करने के पूर्व हमारे भूमि व भवन का सर्वे व नापी का कार्य प्रारम्भ करना चाहता है, उक्त सर्वे रिपोर्ट पर भूमि मालिक जब यह लिखेगा कि मैं उक्त नापी से संतुष्ट हूँ उसके बाद हमारे पाले से स्थिति निकल जाएगी व एनसीएल प्रबंधन औने पौने दाम पर मूल्यांकन कर राशि हमारे खाते मे डालेगा अथवा ट्रिब्यूनल मे डाल देगा, और वर्षों हाम अपने मकान का मुआवजा पाने के लिए परेशान होंगे। उक्त स्थिति आज भी वार्ड क्र. 10 के अनेको रहवासियों की आज भी हैं जो की खदान मे ही दिन रात पड़े रहते हैं और उनकी

कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। अतः उक्त स्थिति हम सभी की ना हो, इसलिए जब तक एनसीएल प्रबंधन उपरोक्त समस्त बिन्दुओ पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करता तब तक सिंगरौली पुनर्स्थापन मंच नापी की प्रक्रिया का कड़ा विरोध करेगा। उक्त अवसर पर एनसीएल प्रबंधन की ओर से सीएमडी बी. साईराम, निदेशक कार्मिक मनीष कुमार के राजस्व विभाग के अधिकारी एवं पुनर्स्थापन मंच के अध्यक्ष सतीश उम्ल, संजय प्रताप सिंह, श्रुपेंद्र गर्ग, राजेश सिंह, गोपाल जी श्रीवास्तव, चन्दन सिंह, राजेश अग्रहरि, राकेश मिश्रा, अजीत झा, विनोद रघुवंशी, आशीष टंडन, निखिल सिन्हा, संजीव सिंह, ओ.पी.एन सिन्हा, सुमंत सिंह, कुंदन सिंह सहित अन्य वरिष्ठ

सदस्य उपस्थित रहे। एनसीएल के जयंत एवं दुर्धनुआ खदान विस्तार के लिए 9 फरवरी को धारा 9 लगने के बाद मोरवा के लोगो में बसाहट एवं मुआवजा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एनसीएल प्रबंधन से वार्ता एवं विस्थापितों के बसाहट एवं उचित मुआवजा के लिए मोरवा में दो गुट अलग अलग सक्रिय है। एक गुट सिंगरौली पुनर्स्थापना मंच का नेतृत्व सतीश उम्ल कर रहे हैं, जबकि दुसरे गुट सिंगरौली विकास मंच का नेतृत्व दधिदाल सिंह कर रहे हैं। दोनो गुटों में कुछ खास लोगो को छोड़कर दिया जाय तो बाकी सब एक ही है। दोनो ही विस्थापितों को लेकर एनसीएल प्रबंधन से चर्चा कर बसाहट एवं उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं।

# प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस में तीन दिवसीय दीक्षारंभ समारोह संपन्न

प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस की गरिमा के अनुरूप महाविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण बनाए : प्राचार्य डॉ सिंह

सीधी। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार सत्र 2024-25 के नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम अंतर्गत तीन दिवसीय दीक्षारंभ समारोह का आयोजन प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस, संजय गांधी स्मृति शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ 1 जुलाई को अपर कलेक्टर श्री राजेश शाही के मुख्य अतिथि एवं महाविद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता में हुआ। प्रथम दिवस नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं को नई शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली, महाविद्यालय की गतिविधियों, विभिन्न विभागों और संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

द्वितीय दिवस का कार्यक्रम प्रातः 9 बजे महाविद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में 75 प्रतिशत उपस्थिति के



संदर्भ में डॉ. आर.बी.एस. चौहान ने जानकारी दी, सीसीई के संदर्भ में डॉ. उमाकांत साहू, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल के संदर्भ में डॉ. गुलशेर अहमद और छात्रवृत्ति की वृद्ध विवेचना डॉ. विनोद प्रजापति ने की। छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय के सभी विभागों का भ्रमण कराया गया जहां शैक्षणिक स्टाफ एवं विभागों की गतिविधियों से उनका परिचय हुआ। डॉ. अरविंद कुमार त्रिपाठी ने प्रोजेक्टर के संदर्भ में छात्र-छात्राओं को जानकारी दी, कैरियर मार्गदर्शन एवं प्लेसमेंट से संबंधित जानकारी डॉ. विनोद कुमार साकेत

ने दी जबकि इनक्यूबेशन सेंटर संबंधी जानकारी डॉ. राकेश कुमार प्रजापति ने दी। एमसीसी की संपूर्ण जानकारी प्रभारी डॉ. उमाकांत साहू, एनएसएस की जानकारी प्रभारी डॉ. सिद्धार्थ कुमार वर्मा ने दी।

तृतीय दिवस में संवेदीकरण, जागरूकता एवं नशा मुक्ति एवं सूचना का अधिकार तथा छात्रावास के संबंध में प्रभारी अधिकारी डॉ. राम सुरेश भारती ने छात्र-छात्राओं को परिचित कराया। कार्यक्रम पर लैंगिक उत्पीड़न के संदर्भ में डॉ. अरुणा ठाकुर, डॉ. गुलशेर अहमद ने

अधिकारी डॉ. उमेश कुमार विश्वकर्मा ने जानकारी प्रदान की, जबकि महाविद्यालय में बच्चों के बीच अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए डॉ. आरबीएस चौहान ने अनुसंधान क्या है, अनुसंधान की परिक्ल्पना क्या है और अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं आदि के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के अंतिम सत्र में छात्र-छात्राओं से प्रश्न उत्तर के माध्यम से उनके विचार आमंत्रित किए गए।

समापन समारोह के पूर्व नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें अनेक छात्र-छात्राओं ने लोकगीत, कहानी, चुटकुले एवं लोक कला पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. पी के सिंह ने नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए परिसर को साफ सुथरा रखने, कक्षाओं में उपस्थित रहने तथा महाविद्यालय में संचालित हो रहे नवीन

पाठ्यक्रमों इत्यादि की जानकारी देते हुए प्राध्यापकों से भी अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस की गरिमा के अनुरूप महाविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण बनाए। त्रि दिवसीय कार्यक्रम के संबंध में डॉ. आरबीएस चौहान ने आभार प्रदर्शन किया तथा छात्र-छात्राओं को प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस का छात्र बनने की बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अनिल कुमार सिंह, डॉ. आशुतोष पांडे, डॉ. कोमल पांडे, डॉ. रितु साहू एवं डॉ. विभा कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त सीनियर प्राध्यापक डॉ. के एस नेताम, डॉ. प्रभाकर सिंह, डॉ. अनिल कुमार सिंह, डॉ. अरुणा ठाकुर, डॉ. आरएन स्वर्णकार, डॉ. अरविंद त्रिपाठी, डॉ. संतोष सिंह चौहान, डॉ. एके शर्मा एवं महाविद्यालय के समस्त सहायक प्राध्यापक, अतिथि विद्वान, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

## मझौली में नैनो उर्वरक के उपयोग के संबंध में संगोष्ठी आयोजित



सीधी। म.प्र. डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला सीधी एवं इफको के संयुक्त तत्वाधान में मां काली सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र विकासखंड मझौली में नैनो उर्वरक उपयोग के संबंध एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें इफको के जनरल मैनेजर प्रकाश चंद पाटीदार एवं जिला प्रबंधक इफको राजेश मिश्रा द्वारा नैनो उर्वरक जैसे नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी, संगरिका आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही 16 नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के डिब्बे तथा सभी कृषि सखियों को एक-एक बैग भी इफको से दिए गए। कृषि

सखियों से अपेक्षा की गई कि जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसानों को बताएं ताकि यूरिया और डीएपी की जगह पर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। संगोष्ठी में जिला पंचायत सदस्य कृष्ण लाल पयसी, एसडीएम मझौली आर पी त्रिपाठी, विधायक प्रतिनिधि प्रवीण तिवारी, समृद्ध किसान आकाश सिंह, विकासखंड प्रबंधक चंद्रकांत सिंह बघेल एवं समस्त विकासखंड टीम सहित म.प्र. डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रशिक्षित कुल 65 कृषि सखियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

## शासकीय महाविद्यालय मड़वास में दीक्षारंभ कार्यक्रम सम्पन्न



सीधी। शासकीय महाविद्यालय मड़वास में तीन दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। दीक्षारंभ कार्यक्रम के तृतीय दिवस में संवेदीकरण और जागरूकता के बारे में डॉ. लक्ष्मीकांत ने जानकारी दी वही सूचना अधिकार अधिनियम 2005 और लोकसेवा गारंटी अधिनियम की जानकारी डॉ. अनुराग तिवारी ने दी। स्वास्थ्य सुरक्षा परामर्श

और मानसिक स्वास्थ्य के सम्बंध में श्रीमती ममता कुशवाहा ए.एन.एम और श्री प्रदीप पाण्डेय एस.टी.एस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़वास ने जानकारी दी। दीक्षारंभ के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री पवन मिश्रा जनभागीदारी अध्यक्ष शासकीय महाविद्यालय मझौली उपस्थित थे तो विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री रामदयाल

कोल सरपंच ग्राम पंचायत दादर उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री पवन मिश्रा ने सभी छात्रों के उज्वल भविष्य की शुभकामना दी। कार्यक्रम का संचालन डॉ. राजेश पटेल ने किया वही आभार डॉ. संगीता मिश्रा ने व्यक्त किया।

कार्यक्रम में महाविद्यालय के डॉ. दीपक अग्निहोत्री, डॉ. अनुराग तिवारी, डॉ. कमलेश जायसवाल, डॉ. पंकज मिश्रा, डॉ. लक्ष्मीकांत कुशवाहा, डॉ. अमिता खरे, डॉ. निशा सिंह, डॉ. सौरभ गुप्ता, डॉ. ज्योति रजक, डॉ. संगीता मिश्रा, डॉ. सुरेंद्र गुप्ता, श्री प्रवीण साकेत, श्री दीपराज प्रजापति, श्री सुंदरलाल प्रजापति, श्री अनिल केवट सहित नवप्रवेशित छात्रछात्राएं एवं पूर्व छात्र छात्राएं उपस्थित थे।

## क्रिकेट विश्व कप की जीत पर मनाया गया जश्न

सीधी। वारवडोस में भारतीय क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका से टी-20 का विश्व कप जीत कर इतिहास रच दिया जिस हेतु भारतीय क्रिकेट टीम बधाई का पात्र है। इस विजय का जश्न सीधी में भी पटाखों फोड़कर मनाया गया। इस जश्न का आयोजन मुकुटधारी सिंह चौहान पूर्व फुटबाल खिलाड़ी एवं मध्य प्रदेश के फुटबाल संघ के कार्यकारी के सदस्य द्वारा अपने प्रांगण डैनिया में किया गया। इस खुशी के बक अन्य पुराने खिलाड़ियों में जैसे उमापति सिंह गहरवार पूर्व एसडीओ फारेस्ट, देवीचरण शर्मा, विनय सिंह चौहान क्रिकेटर पूर्व सरपंच शैरपुर, शंकरलाल गुप्ता, संतोष सिंह गहरवार, धर्मेश सिंह, शिवबालक चौबे एवं अजय सिंह आदि बहुत से लोग उपस्थित रहे।

## शून्य शक्ति अभियान में 1588 सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत

### प्रत्येक पात्र हितग्राही के सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करायें : कलेक्टर

सीधी। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी की पहल पर सभी पात्र हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिले में शून्य शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गत एक माह में अभी तक 1588 सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत किये गये हैं। विकासखंड कुसमी में 72, मझौली में 240, रामपुर नैकिन में 415, सीधी में 483 एवं सिहावल में 378 सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत किए गए हैं।

कलेक्टर श्री सोमवंशी ने बताया कि केंद्र सरकार एवं राज्य

शासन द्वारा वृद्ध, दिव्यांग एवं कल्याणी महिलाओं की सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिले के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से शून्य शक्ति अभियान का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत ग्रामवार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जहाँ चिन्हित पात्र हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त कर उन्हें पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि ऐसे पात्र हितग्राही जिनका बीपीएल में नाम नहीं होने

के कारण सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत नहीं हो पाई है, उनके पात्रानुसार बीपीएल में नाम जोड़ने की कार्यवाही भी की जा रही है। कलेक्टर ने जिले के सभी हितग्राहियों को लोकसेवा केंद्र के माध्यम से बीपीएल में नाम जोड़ने का आवेदन करने के लिए कहा है। कलेक्टर ने बताया कि पोर्टल के अनुसार जिले में वर्तमान में 18827 हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए संभावित पात्रों की सूची में प्रदर्शित हो रहे हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए उन्हें लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर

द्वारा समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया है कि पूरी विवेकपूर्वकता के साथ इस अभियान का क्रियान्वयन किया जाए जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति हितलाभ से वंचित नहीं रहे। कलेक्टर ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी ग्रामपंचायतों से इस आशय के प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जाएंगे कि आज दिनांक की स्थिति में कोई भी पात्र हितग्राही योजना के हितलाभ से वंचित नहीं है।

## मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारियों की त्वरित प्रतिक्रिया

सीधी। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव द्वारा की सरकार द्वारा पेश किया गया बजट जन कल्याण को समर्पित बजट है। बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है।

सांसद डॉ राजेश मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत किए गए मध्य प्रदेश के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि कर

प्रदेश की जनता को सर्वांगीण विकास का तोहफा दिया। प्रस्तुत बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में 21,144 करोड़ से अधिक की वृद्धि कर आगामी 2 वर्षों में 11 नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान कर श्रवण कुमार का फर्ज बखूबी निभाएंगे। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन एवं पर्यावरण के लिए 4725 करोड़ का प्रावधान किया है। सरकारी कर्मचारियों के



भविष्य निधि के भुगतान की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भत्ते तत्काल और सुगमता से मिलेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया बजट का मैं लोकसभा की जनता जनार्दन की

ओर से अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के महामंत्री और पूर्व विधायक शरदेन्दु तिवारी ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि आगामी 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में विश्व स्तरीय सड़कों का जाल बिछने जा रहा है, जिसमें अटल प्रगति पथ पर 299 किलोमीटर, नर्मदा प्रगति पथ पर 900 किलोमीटर, विन्ध्य एक्सप्रेस वे पर 676 किलोमीटर, मालवा निमाड़ विकास पथ 450 किलोमीटर, बुंदेलखंड विकास पथ 330 किलोमीटर और मध्य भारत विकास पथ को 746 किलोमीटर की विश्व

स्तरीय सड़के मिलने जा रही हैं केवल इतना ही नहीं किसने की आए दुगना करने के लिए प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र के रकबा एक करोड़ हेक्टेयर से अधिक होने वाला है। वर्तमान में सिंचित क्षेत्र का रकबा 50 लाख है, जिसे आगामी वर्षों में बढ़कर 1 करोड़ हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके लिए बजट में 13596 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीधी विधानसभा की विधायक और पूर्व सांसद श्रीमती रीती पाठक ने कहा कि विधानसभा में पेश किए गए बजट की मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। विधानसभा में प्रस्तुत

किया गया बजट डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। इस बजट में 36,567 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट की प्रमुख विशेषता यह रही की इस सत्र में देश की जनता जनार्दन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगाया गया है, लेकिन कोई नया कर ना लगाते हुए भी संसाधनों में 16 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करते हुए प्रदेश को विकसित, समृद्धशाली और जनकल्याणकारी बनाने में कोई कसर कोर कसर नहीं छोड़ी गई है।

## म.प्र. का बजट कोरी घोषणाओं का पिटारा, किसानों युवाओं और महिलाओं के लिए बजट में कुछ भी नहीं: ज्ञान



सीधी। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट केवल कोरी घोषणाओं का पिटारा है इस बजट में किसानों युवाओं महिलाओं को

कुछ नहीं मिला लाडली बहन योजना की राशि नहीं बढ़ाई गई किसानों को धान और गेहूँ पर बोनस देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में है सरकार का बजट पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रहा है केवल कर्ज के बोझ तले प्रदेश की आम जनता को झोंकने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है भाजपा की नीतियों के कारण मध्य प्रदेश दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है।

## मध्य प्रदेश को कर्जदार प्रदेश बनाया: कमलेश्वर

मप्र सरकार का बजट प्रदेश को ओर कर्जदार बनाने की दिशा में बढ़ता कदम है

सीधी। प्रदेश की जनता की स्वीकृति के बिना ही ऋण पर ऋण लेकर जनता जनार्दन को कर्जदार बनाया जा रहा है, यह बजट जन विरोधी एवं आमजन को निराश करने वाला है। कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य एवं पूर्व मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने प्रेस विज्ञापित के माध्यम से बताया कि भाजपा सरकार को प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर तत्काल श्रेत पत्र लाना चाहिए जिससे की जनता जनार्दन वस्तु स्थिति से अवगत हो सके। प्रदेश में वित्तीय संकट है, गरीब और गरीब एवं अमीर और अमीर होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों

और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता से जो चार प्रमुख वादे किए थे, उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया। किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपया प्रति क्विंटल। किसानों को गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपया प्रति क्विंटल। धरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपये में। लाडली बहन योजना में महिलाओं को प्रति महीने 3 हजार रुपया। यह बजट पूरी तरह युवा, महिला, श्रमिक, किसान एवं आमजन विरोधी है। श्री पटेल ने कहा कि बजट में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी को दूर करने व नये रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना को प्रस्तुत नहीं किया जा बताया है कि सरकार हर क्षेत्र में विफल व दिशाहीन सरकार है।

## विकास खण्ड कुसमी में शिक्षा विभाग की खण्ड स्तरीय समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन

गुणवत्तायुक्त, सर्वोन्मुखी शिक्षा प्रदान कर बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास करने पर जोर दिया गया

सीधी। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के मार्गदर्शन में सीएम राइज विद्यालय कुसमी के सभागार में 03 जुलाई को सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग डॉ. डी के द्विवेदी तथा जिला शिक्षा केंद्र के सहायक परियोजना समन्वयक अकादमिक विष्णु पाण्डेय, सहायक परियोजना समन्वयक आईईडी रजनीश श्रीवास्तव एवं सहायक यंत्रि सत्य प्रकाश शुक्ला सर्व शिक्षा अभियान एवं अंगिरा प्रसाद द्विवेदी बीआरसीसी कुसमी द्वारा कुसमी विकास खण्ड के समस्त प्राचार्य, जन शिक्षक, प्रमोदनाथपाक तथा मनीटरिंग अधिकार के साथ खण्ड स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में गुणवत्तायुक्त, सर्वोन्मुखी शिक्षा प्रदान कर बच्चों



2024-25 हेतु साइकिल हेतु पात्र बच्चों के सत्यापन की समीक्षा की गई। कक्षा 1 एवं 2 के छात्रों का पंजीयन/सत्यापन, अध्यापन कार्य आदि की समीक्षा की गई।

सभी की अवगत कराया गया। सहायक आयुक्त डॉ. द्विवेदी द्वारा बच्चों का भविष्य संवारने हेतु गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तथा अध्यापन कार्य पर सर्वाधिक जोर दिया गया। कक्षा में शिक्षक बच्चों के बीच सक्रिय रहकर उत्तम अध्यापन कार्य करने, समय से समय तक शाला संचालित करने, शाला तथा शाला परिसर सदा स्वच्छ रखने, कक्षा 1

से 12वीं तक के अच्छे परीक्षा परिणाम हेतु शुरू से ध्यान देने पर विशेष रूप से जोर दिया गया। एपीसी श्री पाण्डेय द्वारा प्रतिदिन बोलकर लिखने हेतु प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही लक्ष्य निर्धारित कर शतप्रतिशत छात्रों के लिए योजना बनकर गुणवत्ता सुधार के लिए सफलता प्राप्त करने हेतु सुझाव दिए गए। जिस शाला भवन की स्थिति ठीक नहीं है, उन शाला भवनों में कक्षाएं संचालित नहीं किये जाने के निर्देश दिए गए और निर्देशित किया गया कि नजदीकी शासकीय, कक्षाएं संचालित नहीं किये जाने के निर्देश दिए गए और निर्देशित किया गया कि नजदीकी शासकीय, किसी भी स्थिति में छात्रों की सुरक्षा करना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। सभी जनशिक्षकों को प्रतिदिन कम से कम 3 विद्यालय का अवलोकन करने हेतु

निर्देशित किया गया। भविष्य में शैक्षणिक कार्य में लापरवाही करने पर सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है। उल्लस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत मूलभूत जानकारी प्रदान की गई तथा प्रत्येक शाला प्रभारी को अपने बसाहट क्षेत्र में घर- घर जाकर असाक्षरों का चिन्हांकन करने, साक्षरता पंजी संधारित कर असाक्षरों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में दर्ज करने एवं एनआईएलपी एम में समस्त असाक्षरों का शत प्रतिशत पंजीयन करने हेतु निर्देशित किया गया। आज की बैठक में मध्यम-मध्यम भोजन के नियमित संचालन हेतु विशेष निर्देश दिए गए। साथ ही 15544 में एसएमएस करने तथा प्रतिदिन फोटो भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

संपादकीय न्याय की ओर

अखिलेश जीत से अहंकार नहीं पालें, बीजेपी के हथ्र से लें सबक

तीन नए आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लागू होना सुखद व स्वागतयोग्य है। इसके साथ ही भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव का दौर शुरू हो गया है। औपनिवेशिक युग के निर्मित या आम नागरिक विरोधी कानूनों को समाप्त करने की मांग लंबे समय से हो रही थी और अंततः अब पुलिस को अनुशासित के साथ-साथ कारगर बनाने की ओर देश ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। पुलिस को अब सबसे पहले यह ध्यान में रखना होगा कि कोई भी कानून अगर लागू हो, तो सभी पर समान रूप से लागू हो। पुलिस प्रशासन की सफलता इसी में है कि तमाम लोगों को यह महसूस हो कि कानून न्यायपूर्ण ढंग से लागू किया जा रहा है। एक पहलू यह भी है कि पुलिस प्रशासन को कुशल और सक्षम बनाने के लिए संसाधनों की कमी आड़े नहीं आए, जिस स्तर की सेवा की उम्मीद लोग पुलिस से कर रहे हैं, उसके लिए सरकारों को पुलिस पर व्यय बढ़ाना होगा। सक्षम और सहयोगी पुलिस हमारे तेज विकास में कारगर होगी। ध्यान रहे, पिछले कानूनों में यह बड़ी कमी थी कि उनका इस्तेमाल गरीबों के खिलाफ जितनी आसानी से होता था, उससे कहीं ज्यादा कठिनाई से अमीरों के खिलाफ मामले दर्ज होते थे। आरोप सिद्ध होने या सजा के मामले में भी गरीबों को ही ज्यादा भुगताना पड़ता था। हम बार-बार कह रहे हैं कि इन तीन कानूनों ने ब्रिटिश काल के तीन कानूनों की जगह ले ली है, तो जमीन पर वास्तव में लोगों को यह एहसास करना होगा कि ब्रिटिश हिस्सेब से बने कानून अब देश में नहीं चल रहे हैं। नए कानूनों में यह ताकत है कि इनसे अपने वहां संपूर्ण न्याय प्रणाली में आम नागरिकों के अनुरूप आधुनिक बदलाव हो सकता है। ज़ीरो एफआइओ, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, एमएसएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सम्मन और सभी जन्य अपराधों के लिए अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान ज्यादा कारगरता के साथ लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने अपना काम कर दिया है और अब राज्यों को अपने स्तर पर इन अच्छे कानूनों को लागू करने की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और देश के ज्यादातर राज्यों में पुलिस जिस तरह से प्रशिक्षित हो रही है।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के हौसले इस समय काफ़ी बुलंद हैं। उनकी पार्टी ने यूपी की 80 में से 37 सीटों पर जीत हासिल की है। इसी के बाद वह यूपी में 2014 के लोकसभा चुनाव में 71 और 2019 में 62 और अबकी 2024 में 33 सीटें एवं यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में 312 तथा 2022 में 273 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर है। ऐसा होना स्वभाविक भी है, उन्हें (अखिलेश यादव) अपने नेतृत्व में पहली बार लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत का स्वाद चखने को मिला है। इससे पहले अखिलेश की जीत रिकार्ड ना के बराबर था। वह समाजवादी पार्टी की बागडोर संभालने के बाद लगातार जीत के लिये तरस रहे थे। 2012 के विधानसभा चुनाव, जो समाजवादी पार्टी द्वारा मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में लड़े गये थे गये थे, उसमें समाजवादी पार्टी को बहुमत हासिल हुआ था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुलायम ने अपनी जगह बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया था, जिसका लेकर पार्टी में मनमुटाव भी देखने को मिला था। तब से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी यूपी से लेकर दिल्ली तक के चुनाव में अपनी पैठ नहीं बना पाई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा को यूपी की 80 सीटों में से मात्र 05 सीटों पर एवं 2019 में सीटों पर जीत हासिल हुई थी। सपा ने 2019 का लोकसभा चुनाव बसपा के साथ मिलकर और अबकी 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था। वहीं 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव जो उसने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था उसमें सपा को मात्र 47 सीटों पर संतोष करना पड़ा था और 2022 में भी बहुत अच्छा करने के बाद भी 125 सीटों पर उसकी जीत का आकड़ा ठहर गया था।



2022 में 273 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर है। ऐसा होना स्वभाविक भी है, उन्हें (अखिलेश यादव) अपने नेतृत्व में पहली बार लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत का स्वाद चखने को मिला है। इससे पहले अखिलेश की जीत रिकार्ड ना के बराबर था। वह समाजवादी पार्टी की बागडोर संभालने के बाद लगातार जीत के लिये तरस रहे थे। 2012 के विधानसभा चुनाव, जो समाजवादी पार्टी द्वारा मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में लड़े गये थे गये थे, उसमें समाजवादी पार्टी को बहुमत हासिल हुआ था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुलायम ने अपनी जगह बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया था, जिसका लेकर पार्टी में मनमुटाव भी देखने को मिला था। तब से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी यूपी से लेकर दिल्ली तक के चुनाव में अपनी पैठ नहीं बना पाई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा को यूपी की 80 सीटों में से मात्र 05 सीटों पर एवं 2019 में सीटों पर जीत हासिल हुई थी। सपा ने 2019 का लोकसभा चुनाव बसपा के साथ मिलकर और अबकी 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था। वहीं 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव जो उसने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था उसमें सपा को मात्र 47 सीटों पर संतोष करना पड़ा था और 2022 में भी बहुत अच्छा करने के बाद भी 125 सीटों पर उसकी जीत का आकड़ा ठहर गया था।

लिव्बोलुआब यह है कि अखिलेश को सपा का नेतृत्व संभाले दस वर्ष हो चुके हैं। इन दस वर्षों में सपा को चार बड़ी हार और कई छोटी-छोटी हार का भी सामना करना पड़ा था। दस वर्षों के बाद पहली बार 2024 के आम चुनाव में में उनकी पार्टी की जीत का ग्राफ बढ़ा जरूर है, लेकिन यह बहुत इतनी नहीं थी, जितना सपा प्रमुख द्वारा प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। भाजपा की यूपी में चार सीटें ही समाजवादी पार्टी से कम आई हैं और इसकी वजह बीजेपी के प्रति जनता की नाराजगी से अधिक उसके (बीजेपी) भीतर की खींचतान थी। बहरहाल, अखिलेश अपने हिस्सेब से राजनीति करने के लिये स्वतंत्र हैं, लेकिन उनका अहंकार उचित नहीं है। जीत की खुशी में किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता है। दुखद यह है कि अखिलेश यादव जाने-अजाने ऐसा कर रहे हैं, जिस तरह मुलायम सिंह ने सत्ता में रहते कारसेवकों पर गोली चलाई और फिर इसके महिमामंडित किया था, उसी तरह से आज अखिलेश यादव अयोध्या से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत के बाद कर रहे हैं। इसके

लिये वह सीधे तौर पर तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनके संकेत की राजनीति का यही निचोड़ नजर आता है कि आज भी समाजवादी पार्टी प्रभु श्रीराम की विरोधी है। यहाँ तक की संसद में भी अखिलेश ऐसा ही कर रहे हैं। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने सदन में बोलते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला, इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं थी। अखिलेश ने पेपर लोक मुद्दा, अयोध्या, जाति जनगणना, एमएसपी, ओपीएस, अग्निवीर योजना जैसे कई मुद्दों के सहारे बीजेपी सरकार को घेरा तो यूपी का जिन्न करते हुए कहा कि जुमला बनाने वालों से विश्वास उठ गया। सपा प्रमुख ने पेपर लोक मामले को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। कहा कि यूपी में परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है। पेपर लोक मुद्दे पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, पेपर लोक क्यों हो रहे हैं? सच तो यह है कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उसे युवाओं को नौकरी न देनी पड़े। वहीं इवीएम पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, इवीएम पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं है भरोसा, मैं 80 में 80 सीटें जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा

होगा। वह बोले इवीएम का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। अखिलेश कहते हैं कि यहाँ हारी हुई सरकार विराजमान है। ये चलने वाली नहीं गिरने वाली सरकार है। आवाम ने हुकुमत का गुरूर तोड़ा जनता कह रही, सरकार गिरने वाली है। संविधान रक्षकों की जीत हुई है। अखिलेश ने कहा, देश के सभी समझदार और ईमानदार मतदाताओं को धन्यवाद जिन्होंने देश के लोकतंत्र को एकत्रित बनाने से रोका। आवाम ने तोड़ दिया हुकुमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर। सपा प्रमुख ने कहा, कहने को यह सरकार कहती है कि ये फिफथ लाजेंट इकोनॉमी बन गई है, लेकिन यह सरकार क्यों छुपती है हमारे देश की पर कैपिटल इनकम किस स्थान पर पहुंची है? वर्ल्ड हॉर इंडेक्स पर कहां खड़े हैं, नीचे से कहां हैं? मगर जब अखिलेश से राहुल गांधी के हिन्दुओं को हिंसक बताने जाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया मांगी जाती है तो वह इधर-उधर की बात करने लगते हैं। खैर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बातों में दम तो लगता है, लेकिन वह यह नहीं याद रखते हैं कि समाजवादी पार्टी में किस तरह से नकल माफिया सक्रिय रहते थे। सरकारी नौकरियों निकलने से पहले इनकी भर्ती के लिये सोदा हो जाता था। दबंग समाजवादी नेता कैसे थानों थानों पर 'कब्जा' कर लेते थे। सरकारी टेंडर के लिये कैसे खून-खराबा होता था। भू माफिया किस तरह से जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। लड़कियों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया था। कानून व्यवस्था के नाम पर जंगलराज फैल गया था। इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने 2017 के विधान सभा चुनाव में सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया था। अखिलेश पर हिन्दुओं को दलित, ओबीसी के नाम पर बांटने पर भी आरोप लगता रहता है, परंतु वह इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। वह यह भी नहीं बताने हैं कि पूर्व सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव जिस कांग्रेस में हमेशा दुरी बनाकर चलते थे, उससे उन्होंने कैसे हाथ मिला लिया। अखिलेश तो कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव आम चुनाव में मिली जीत से आनंदित होते, लेकिन वह आनंदित से अधिक अहंकार में डूबे ज्यादा नजर आ रहे हैं, जबकि वह अहंकार में डूबी बीजेपी का हथ्र देख चुके हैं।

धार्मिक आयोजनों में कब रुकेंगे ऐसे दुखद हादसे

(पंकज सिंह) फिर एक बार दुखद हादसा घटित हो गया। हाथरस कोई पहला मामला नहीं इसके पहले भी धार्मिक आयोजनों में हुई भगदड़ जैसे दुखद हादसे घट चुके हैं। सवाल यह है कि यह कब रुकेंगे। हर बार की तरह ये सवाल सामने आने लगे हैं कि हादसे का जिम्मेदार कौन ? प्रशासन ने कितने लोगों की अशुभमति दी थी ? मंगलवार 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आयोजित एक सत्संग में मंगलवार को भगदड़ मच गई, जिसमें 134 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। भारत में मंदिरों और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ होने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत की यह पहली घटना नहीं है। महाराष्ट्र के मंधारदेवी मंदिर में 2005 के दौरान हुई भगदड़ में 340 श्रद्धालुओं की मौत और 2008 में राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर हुई भगदड़ में कम से कम 250 लोगों की मौत ऐसी ही कुछ बड़ी घटनाएँ हैं। हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में भी 2008 में ही धार्मिक आयोजन के दौरान मची भगदड़ में 162 लोगों की जान चली गई थी। हाल के वर्षों में देश में मंदिरों और धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ की कुछ प्रमुख घटनाएँ इस प्रकार हैं।



'पुकरम' उत्सव के पहले दिन गोदावरी नदी के तट पर एक प्रमुख खान स्थल पर भगदड़ से 27 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई तथा 20 अन्य घायल हो गए। 3 अक्टूबर 2014 - दशहरा समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मचने से 32 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। 13 अक्टूबर 2013 - मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 115 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भगदड़ की शुरुआत नदी के पुल टूटने की अफवाह से हुई जिसे श्रद्धालु पार कर रहे थे। 19 नवंबर 2012 - पटना में गंगा नदी के तट पर अदालत घाट पर छठ पूजा के दौरान एक अस्थायी पुल के ढह जाने से मची भगदड़ में

लगभग 20 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। 8 नवंबर 2011 - हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर हरकी पैड़ी घाट पर मची भगदड़ में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। 14 जनवरी 2011 - केरल के इडुक्की जिले के पुलमेडु में एक जीप के सवारीमाला मंदिर के दर्शन कर लौट रहे तीर्थयात्रियों से टकरा जाने के कारण मची भगदड़ में कम से कम 104 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 40 से अधिक घायल हो गए। 4 मार्च 2010 - उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कृपालु महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मचने से लगभग 63 लोगों की मौत हो गई। लोग स्वयंभू धर्मगुरु द्वारा दान किए जा रहे कपड़े और भोजन लेने पहुंचे थे। 30 सितंबर 2008 - राजस्थान के जोधपुर शहर में

चामुंडा देवी मंदिर में बम विस्फोट की अफवाह के कारण मची भगदड़ में लगभग 250 श्रद्धालु मारे गए और 60 से अधिक घायल हो गए। 3 अगस्त 2008 - हिमाचल प्रदेश के खिलासपुर जिले में नैना देवी मंदिर में चढ़ान खिसकने की अफवाह के कारण मची भगदड़ में 162 लोगों की मौत हो गई, 47 घायल हो गए। 25 जनवरी 2005 - महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंधारदेवी मंदिर में वार्षिक तीर्थयात्रा के दौरान 340 से अधिक श्रद्धालुओं की कुचलकर मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। यह दुर्घटना तब हुई जब कुछ लोग फिसलन भरी सीढ़ियों पर गिर गए। 27 अगस्त 2003 - महाराष्ट्र के नासिक जिले में सिंहस्थ कुंभ मेले में पवित्र खान के दौरान भगदड़ में 39 लोग मारे गए और लगभग 140 घायल हो गए।

Table with title 'गर्ग पहली 5420' and 'गर्ग पहली 5419 का हल'. The table contains numbers in a grid format for a lottery or game. Below the table are lists of numbers and instructions in Hindi.

नये भारत में बदलाव के कानून, न्याय की ओर

ललित गर्ग भारतीय न्याय प्रणाली की कमियाँ को दूर करते हुए उसे अधिक चुस्त, त्वरित एवं सहज सुलभ बनाना नये भारत की अपेक्षा है। मतलब यह सुनिश्चित करने से है कि सभी नागरिकों के लिये न्याय सहज सुलभ महसूस हो, कानूनी प्रावधान न्यायसंगत एवं अपराध-निंत्रण का माध्यम हो, वह आसानी से मिले, जटिल प्रक्रियाओं से मुक्त होकर सरता हो। निश्चित रूप से किसी भी कानून का मकसद नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति व अधिकारों की रक्षा करना ही होता है। जिससे किसी सभ्य समाज में न्याय की अवधारणा पुष्ट हो सके। 1 जुलाई, 2024 से भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। न्याय का एक नया सूरज उदित हो रहा है, जब पूरे देश में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य संहिता को लेकर उम्मीद करनी चाहिए कि यह बदलाव न्याय की कसौटी पर खरा उतरेंगे। इस दृष्टि से यह कानून से जुड़ी अकल्पित उपलब्धियों से भरा-पूरा अवसर भारत न्याय प्रक्रिया को एक नई शक्ति, नई ताजगी और नया परिवेश देने वाला साबित होगा। उल्लेखनीय है कि कानूनी बदलाव से जुड़े ये तीनों विधेयक बीते साल संसद में पारित किये गए थे। अग्रेजों के बनाये कानून क्या स्वतंत्र भारत में साढ़े सात दशक बाद भी लागू रहने चाहिए, यह लंबे समय से विमर्श का विषय बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार द्वारा न्यायिक व्यवस्था को भव्यी, आधुनिक, तकनीकी बनाने के लिये, अप्रसंगिक हो चुके कानूनों को बदलने एवं आधुनिक अपेक्षाओं के नये कानून बनाने का साहसिक एवं प्रासंगिक कदम उठाते हुए

नए कानून लाने एवं उन्हें लागू करने का बड़ा कदम उठाया है, जो सुखद एवं स्वागतयोग्य है। विपक्षी दलों ने सांस्कृतिक, धार्मिक व भौगोलिक विविधता वाले देश के लिये बनाये गये कानूनों को भले ही व्यापक सार्वजनिक विमर्श के बाद ही लागू किया जाने की अपेक्षा व्यक्त की हो, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जहाँ ब्रिटिश काल में बने कानूनों का मकसद ढंढ देना था, वहीं नये कानूनों का मकसद नागरिकों को न्याय देना है। मौजूदा चुनौतियों व जरूरतों के हिसाब से कानूनों को बनाया गया है। इन कानूनों को बनाने का मूल उद्देश्य अपराधमुक्त समाज की संरचना करना है। इसीलिये अपराधियों को कड़े दण्ड देने का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय न्याय संहिता में विवाह का प्रलोभन देकर छल के मामले में दस साल की सजा, किसी भी आधार पर मौं बलिहारी के मामले में आजीवन कारावास की सजा, लूटपाट व गिरोहबंदी के मामले में तीन साल की सजा का प्रावधान है। आतंकवाद पर नियंत्रण के लिये भी कानून है। किसी अपराध के मामले में तीन दिन में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी तथा सुनवाई के बाद 45 दिन में फैसला देने की समय सीमा निर्धारित की गई है। वहीं प्राथमिकी अपराध व अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के जरिये दर्ज की जाएगी। व्यवस्था की गई है कि लोग थाने जाए बिना भी ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कर सकें। यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इन कानूनों के माध्यम से देश में पुलिस सुधार को भी बल मिलेगा। पुलिस कानून-कायदे के तहत काम करने को विवश या बाध्य होगी। अंततः अब पुलिस को अनुशासित बनाने के साथ-साथ कारगर बनाने की ओर देश ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। पुलिस प्रशासन की

आज का राशिफल

Table with 4 columns: राशि (Sign), गुण (Quality), वृषभ (Taurus), and कर्क (Cancer). Each cell contains a brief horoscope reading in Hindi for that sign and quality.

Table with 4 columns: राशि (Sign), गुण (Quality), तुला (Libra), and वृश्चिक (Scorpio). Each cell contains a brief horoscope reading in Hindi for that sign and quality.

संक्षिप्त समाचार

नोएडा में 12 और स्थानों पर लगेगी पार्किंग फीस, जाने बाइक से कार तक कितना होगा चार्ज



नई दिल्ली, एजेंसी। नोएडा शहर में फेज-2 समेत 12 और स्थानों पर इस महीने से पार्किंग फीस वसूलने की तैयारी है। इनके लिए जारी किए गए टेंडर को बुधवार को खोला जाएगा। अभी करीब 35 स्थानों पर सड़क पर पार्किंग चल रही है। नए टेंडर नहीं होने के कारण करीब एक साल तक शहर में सरफेस पार्किंग बंद रही थी। ऐसे में लोगों को मुफ्त में पार्किंग की सुविधा मिल रही थी। करीब सात महीने से दोबारा से शुल्क लिए जाने की शुरुआत हो गई थी। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पिछले दिनों वलस्टर नंबर-4 के अंतर्गत सेक्टर-81, फेज 2, सेक्टर-83, 88 में पार्किंग शुरू करने के लिए टेंडर जारी किया गया था। वलस्टर नंबर-7 के अंतर्गत होजरी कॉम्प्लेक्स और वलस्टर नंबर-6 के अंतर्गत सेक्टर-80 के भूखंड संख्या बी-46 में भी पार्किंग शुरू की जानी है। इन पार्किंग से संबंधित टेंडर में कंपनियों के आवेदन करने का मंगलवार को आखिरी दिन था। अब टेंडर बुधवार को खोला जाएगा। अगर टेंडर में आई एजेंसियां मानक पूरा करती हैं तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए प्राइज बिड खोली जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि अगर किसी टेंडर प्रक्रिया में एजेंसियों का चयन हो जाता है तो इस महीने के अंत या अगस्त की शुरुआत से संबंधित स्थानों पर पार्किंग शुरू वसूला जाना शुरू कर दिया जाएगा। पार्किंग शुरू होने से सड़क मार्ग पर अव्यवस्थित खड़े वाहनों के कारण लगने वाले जाम से छुटकारा मिलेगा। प्राधिकरण को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। सीईओ के निर्देश पर नोएडा ट्रैफिक सेल ने शहर में नए स्थानों पर पार्किंग शुरू करने के लिए सर्वे किया था। सर्वे में ऐसे करीब 19 स्थान सामने आए थे। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इन स्थानों पर पार्किंग शुरू करने के लिए जल्द टेंडर जारी किए जाएंगे।

पति मरा पड़ा मिला, तीन बच्चों के साथ पत्नी गायब, टूटी चूड़ियां से गहराया शक

नई दिल्ली, एजेंसी। ग्रेटर नोएडा के बिरांडा गांव के पास बने सुलभ शौचालय की छत पर केयरटेकर का शव सड़िध परिस्थितियों में पड़ा मिला। घटना के बाद से मृतक की पत्नी अपने तीन बच्चों के साथ गायब है। पत्नी पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की टीम पत्नी की तलाश में जुटी है। मूलरूप से हमीरपुर का रहने वाला महेश कुमार बिरांडा गांव में अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहता था। महेश कुमार गांव के समीप बने सुलभ शौचालय के केयरटेकर का काम करता था। सोमवार की शाम महेश का शव सुलभ शौचालय की छत पर पड़ा मिला। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महेश कुमार की नाक से खून निकलने के निशान मिले हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। ग्रेटर नोएडा पुलिस के मुताबिक महेश की पत्नी पूजा घटना के बाद से अपने तीन बच्चों को लेकर गायब है। पुलिस की टीम महेश के घर पहुंची तो उसकी पत्नी और बच्चे वहां नहीं मिले। घटनास्थल पर कुछ चूड़ियां टूटी पड़ी मिली हैं। आशंका है कि पत्नी की हत्या की है। पुलिस की टीम महिला की तलाश में जुटी है। महिला से पूछताछ के बाद ही घटना का खुलासा हो सकेगा। पुलिस की दो टीमों में महिला की तलाश में जुटी है। पुलिस की टीमों में महिला के कई ठिकानों पर दबिश दी है। महिला मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली बताई जा रही है। हालांकि, अभी महिला का कोई सुरांग नहीं लगा है। पुलिस का दावा है कि महिला को जल्द हिरासत में लेकर घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। एडीसीपी अशोक कुमार ने कहा कि केयरटेकर की मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। घटना के बाद से पत्नी गायब है उसकी तलाश कर जा रही है। उसके मिलने पर मामले से पर्दा उठेगा। इस घटना में पुलिस कई बिडुआओं को लेकर जांच कर रही है। प्रेमप्रसंग को लेकर भी हत्या की आशंका जताई जा रही है। आशंका है कि महिला के साथ कोई और भी घटना में शामिल हो सकता है। अवैध संबंध को लेकर भी जांच की जा रही है। महिला के पकड़ने जाने पर ही मामले का खुलासा होगा।

दिल्ली में 600 से अधिक लोगों को ठगने वाला अरेस्ट, 4.25 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने राष्ट्रीय राजधानी में 600 से अधिक लोगों को ठगने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निवेश पर भारी मुनाफे का लालच देकर धोखाधड़ी का शिकार होने वाले कई पीड़ितों की शिकायतों पर 2021 में मुकदमा दर्ज किया गया था। अधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपी चंद्र प्रकाश सैनी और अन्य ने वसुंधरा समूह और अनकाय निधि के नाम पर कई वित्त कंपनियों चलाई तथा कम आय वाले परिवारों को रोजाना निवेश वाले बचत खाते, सार्वजनिक खाते और अन्य आकर्षक निवेश योजनाओं में पैसा लगाने का लालच दिया। ईओडब्ल्यू के पुलिस उपायुक्त अनुरोध रॉय ने बताया कि जांच के दौरान सह-आरोपी निदेशक (चंद्र प्रकाश सैनी की पत्नी) सुनीता सैनी को 2022 में गिरफ्तार किया गया।

अब डीडीसीडी को भंग करने पर रत्न और मंत्री आमने-सामने, आतिशी बोलीं- उनके अधिकार से यह बाहर

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की योजना मंत्री आतिशी ने सेवा विभाग और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के उस आदेश को शून्य बताया है, जिसमें उन्होंने डीडीसीडी (दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग) के गैर-आधिकारिक सदस्यों को हटाने का कहा था। आतिशी ने कहा कि वह आदेश उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, इसलिए एलजी के आदेश के बावजूद गैर-आधिकारिक सदस्य अपनी भूमिका में बने रहेंगे। इससे पहले बीते महीने उपराज्यपाल ने डीडीसीडी को अस्थायी रूप से भंग करने और इसके गैर-आधिकारिक सदस्यों को हटाने की मंजूरी दी थी, जब तक कि इसके उपाध्यक्ष और सदस्यों के रूप में डोमेन विशेषज्ञों की स्क्रीनिंग और चयन के लिए एक तंत्र विकसित नहीं हो जाता। आतिशी द्वारा जारी आदेश प्रमुख सचिव (योजना), प्रमुख सचिव (सेवाएं) और मुख्यमंत्री के विशेष सचिव को भेजा गया है। आतिशी के आदेश में कहा गया है कि डीडीसीडी के गठन की शर्तों से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि गैर-आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यों के निर्वहन पर एकमात्र पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार और अधिकार मुख्यमंत्री का है। योजना मंत्री आतिशी ने इस बारे में एक आदेश जारी करते हुए कहा, यह स्पष्ट है कि सेवा विभाग और एलजी का आदेश सत्ता व अधिकार के दुरुपयोग के



स्पष्ट उदाहरण हैं, और साफ तौर पर गलत व धामक हैं। इसके अलावा यह आदेश दोनों के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता है इसलिए कानून की नजर में अमान्य भी है। आतिशी के आदेश में आगे लिखा गया, इसलिए, सेवा विभाग के दिनांक 27/06/2024 के आदेश और एलजी के आदेश को अमान्य घोषित करने हुए 26/06/2024 की यथास्थिति को बहाल की जाती है। इस मामले में विभाग की मंत्री (योजना) की मंजूरी के बिना सेवा विभाग या एलजी के आदेश के अनुसार कोई भी कार्यवाही

अवैध मानी जाएगी और दोषी अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। आतिशी ने अपने आदेश में कहा कि डीडीसीडी का गठन दिल्ली की निर्वाचित सरकार यानी मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया है। आदेश में कहा गया, यह स्पष्ट है कि एलजी के पास हस्तांतरित विषयों पर कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। ऐसे मामलों में वह निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह से बंधे होते हैं, जो हस्तांतरित विषयों पर विशेष कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करती है, जिसमें

योजना विभाग से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं, जो जीएनसीटीडी का प्रशासनिक विभाग है। अपने आदेश में आतिशी ने कहा, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि गैर-आधिकारिक सदस्यों को सीधे मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाना है, उनका कार्यकाल दिल्ली एनसीटी सरकार के कार्यकाल के साथ समाप्त होता है और उन्हें केवल डीडीसीडी के अध्यक्ष, जो कि मुख्यमंत्री हैं की मंजूरी से ही हटाया जा सकता है। योजना विभाग की मंत्री द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, प्रथम दृष्टया एलजी के पास इन गैर-आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश जारी करने का कोई अधिकार या शक्ति ही प्राप्त नहीं है। आगे आतिशी ने जोर देकर कहा कि एलजी और सेवा विभाग के पास डीडीसीडी के गैर-आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति या उन्हें हटाने से जुड़ा कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आदेश में कहा कि वे डीडीसीडी या इसके गैर-आधिकारिक सदस्यों पर कोई पर्यवेक्षी नियंत्रण नहीं रखते हैं। आतिशी ने कहा कि गैर-आधिकारिक सदस्य सेवा विभाग के दायरे में नहीं आते हैं क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि डीडीसीडी के गैर-आधिकारिक सदस्यों को किसी सिविल सेवा में नियुक्त नहीं किया जाता है, न ही वे किसी सिविल पद पर होते हैं।

दिल्ली में हीटस्ट्रोक की वजह से हुई 28 मोर की मौत ?



नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के पालम एयर बेस पर पिछले महीने 28 मोर की मौत होने से हड़कंप मच गया। हरकत में आए वन एवं वन्यजीव विभाग ने उनकी जांच की। जिसमें चार किसी भी तरह के वायरस संक्रमित नहीं मिले। माना जा रहा है कि हीटस्ट्रोक के कारण उनकी मौत हुई। विभाग का कहना है कि 28 जून को भारी बारिश की वजह से तापमान में कमी आने के बाद एयरबेस पर किसी मोर की मौत की सूचना नहीं मिली है। एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने कहा, हमने पिछले हफ्ते चार मृत मोर के शव दिल्ली चिड़ियाघर भेजे थे और चार मोर के नमूने बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) भेजे थे। रिपोर्ट आ गई है और वहां किए गए वायरोलॉजी टेस्ट में कोई वायरल बीमारी नहीं मिली है। हमें 28 जून के बाद एयरबेस पर किसी भी मोर की मौत की सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि टीमें साइट की निगरानी करना जारी रखेंगी। वन अधिकारी ने बताया कि हीटस्ट्रोक मौत का एकमात्र कारण नहीं है, पोस्टमार्टम में मिमोसिना और हेपेटोसिस (लिवर का एक विकार) भी मिला है, जो दो मोर की मौत का कारण है। अधिकारी ने कहा, हमारा मानना है कि ज्यादातर मौतें हीटस्ट्रोक की वजह से हुईं, क्योंकि दिल्ली में बारिश के बाद मौतें रुक गई हैं। हमने वहां भी एहतियाती कदम उठाए हैं। वन एवं वन्यजीव विभाग ने 25 जून को पालम एयरबेस स्टेशन का निरीक्षण किया तब वहां तीन मृत मोर मिले थे। विभाग ने रिपोर्ट जारी कर बताया कि 4 से 25 जून के बीच वहां 27 मोर की मौत हुई। एक दिन बाद एक और मोर मृत मिला। घटना की रिपोर्ट में बताया गया है कि 4 जून, 6 जून, 11 जून और 12 जून को एक-एक मौत की सूचना मिली थी। 13-15 जून के बीच दो-दो मौतें हुईं।

अंतिम संस्कार के 53 दिन बाद नोएडा में जिंदा मिली भिंड की ज्योति, लाइली बहना योजना के पैसों से हुआ खुलासा

नई दिल्ली, एजेंसी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में ज्योति शर्मा समझकर जिस महिला के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, वह 53 दिन बाद नोएडा में टूटी चप्पल जुड़वाते हुए मिली। महिला ने लाइली बहना योजना से मिले रुपये अपने बैंक खाते से निकाले तो इसका खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक, भिंड के मेहगांव में रहने वाली ज्योति शर्मा 2 मई को घर से लापता हो गई थी। पति सुनील शर्मा ने ज्योति की गुमशुदगी की रिपोर्ट मेहगांव थाने में दर्ज कराई थी। गुमशुदगी दर्ज होने के दो दिन बाद एक महिला का मो थाने के कतरील गांव के पास खेत में जला हुआ शव मिला। पुलिस ने शव की शिनाख्त करने के लिए ज्योति शर्मा के मायके और ससुराल पक्ष के लोगों को घटनास्थल पर बुलाया। मायके पक्ष के लोगों ने लाश की शिनाख्त ज्योति शर्मा के रूप में की, लेकिन ज्योति का पति सुनील शर्मा शव को किसी और महिला का बताता रहा। ज्योति के मायके पक्ष और पुलिस के दबाव के चलते पति सुनील शर्मा ने शव को अपनी सुपुदगी में ले लिया और फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अस्थि विसर्जन और तेह्रवें तक करा दी गई। पति पर लगाया हत्या का आरोप - बताया जाता है कि महिला के मायके वालों ने उसके पति सुनील शर्मा पर ज्योति शर्मा की हत्या का आरोप लगाया। जिस कतरील गांव में महिला का शव मिला, वह ज्योति शर्मा की ससुराल वालों का पेटक गांव है।

7 जुलाई तक 18 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। मौसम विभाग के द्वारा ताजा रिपोर्ट जारी की गई है। दक्षिण-पूर्वी पकिस्तान पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। मौसम की ट्रॉपिका समुद्र तल पर अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर है। इसके कारण अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं, आईएमडी ने कुछ राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 4 से 7 जुलाई के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान र मुजफ्फरबाद में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, आज से सात जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में जोरदार बारिश का अनुमान है। तीन जुलाई को पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश की बात कही गई है। इसके अलावा, 4 जुलाई तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 3-7 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में जोरदार बारिश होगी। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक, 6-7 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 5-7 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तरी बांग्लादेश पर बना हुआ है और दूसरा असम पर स्थित है। एक ट्रॉपिका पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश से असम के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण तक निचले क्षोभमंडल स्तरों पर बनी हुई है। इसके कारण भी कुछ राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार बने रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 3 से लेकर 7 जुलाई के बीच बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की



एनसीआर के 2 शहरों को बड़ी राहत, गुरुग्राम-फरीदाबाद में अब पार्किंग के साथ बना सकेगें 4 मंजिला भवन

नई दिल्ली, एजेंसी। एनसीआर में आने वाले फरीदाबाद और गुरुग्राम शहर के लोग फिर से स्टिल्ट पार्किंग सहित चार मंजिला (स्टिल्ट+4) भवन बना सकेगें। हरियाणा सरकार ने एक साल बाद इस नीति पर लगाई रोक को कुछ शहरों के साथ हटा दिया है। पुराने कॉलोनियों में भी यह नीति लागू होगी। हरियाणा के नगर एवं आयोजना और शहरी संपदा मंत्री जे.पी. दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंगलवार को यह घोषणा की। सरकार के इस निर्णय से आम जनता को काफी फायदा होगा। जेपी दलाल ने कहा कि एसी कॉलोनियों और सेक्टरों में, जहां लेआउट प्लान प्रति प्लॉट तीन आवासीय इकाइयों के साथ मंजूर है, लेकिन केवल ऐसे आवासीय भूखंडों, जिनके पास 10 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क है, उनमें भी कुछ शहरों के साथ स्टिल्ट+4 मंजिल के निर्माण की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि एसी कॉलोनियों में, जहां व्यक्ति अब एस+4 का निर्माण करना चाहता है, तो उस स्थिति में मालिक को पहले पड़ोसियों से सहमति प्राप्त करनी होगी। यदि पड़ोसी सहमति प्रदान नहीं करते हैं तो वह व्यक्ति साथ लगते मकान से



सभी मंजिलों के लिए 1.8 मीटर की जगह (साइड सेटबैक) छोड़कर एस+4 का निर्माण कर सकता है। हालांकि सरकार ने यह प्रावधान किया है कि यदि पड़ोसी एस+4 के निर्माण के लिए अपनी सहमति नहीं देता है, तो वह स्वयं भी भविष्य में एस+4 का निर्माण करने के लिए अपात्र होगा। 250 वर्ग मीटर क्षेत्र से कम के प्लॉटों पर नहीं दी जाएगी। बेसमेंट की अनुमति - जेपी दलाल ने कहा कि किसी भी स्थिति में 10 मीटर चौड़ाई और 250 वर्ग मीटर क्षेत्र से कम के प्लॉटों पर बेसमेंट के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि प्लॉट पर

पहले से 3 मंजिल व बेसमेंट बनाने की अनुमति है तथा अब स्टिल्ट+4 निर्माण की अनुमति ली गई है, तो बेसमेंट के निर्माण और कॉमन दीवार पर भार का डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, ऐसे मामलों में आसपास के प्लॉट मालिकों की आपसी सहमति से बेसमेंट के निर्माण और कॉमन दीवार पर भार डालने की अनुमति होगी। इसके अलावा, यदि बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन और निर्माण के लिए आवासीय प्लॉटों की पूरी पॉकेट को एक बार में बनाया जाता है, तो कॉमन दीवार के निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

कनाडा तक फ्लाइट, फिर डंकी रूट से जाना था अमेरिका, आईजीआई पर पकड़े गए बुजुर्ग ने बताया पूरा प्लान

नई दिल्ली, एजेंसी। विदेश में बेहतर ज़िंदगी और अच्छी जीवनशैली के लालच में फंसकर भारत से कई लोग विदेश जाने की खाहिश रखते हैं। जिसका फायदा उठाकर एजेंट मुहम्मदी रकम मांगकर उन्हें भेजने का झांसा देते हैं। इस चक्कर में कुछ लोग ऐसी हरकत कर देते हैं जो उन्हें सलाहों के पीछे पहुंचा देती है। ऐसा ही कुछ पिछले महीने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिला। जहां 24 साल का युवक मेकअप करके 67 साल का बुजुर्ग बन गया और कनाडा जाने वाली फ्लाइट के लिए चेक-इन करने टर्मिनल-3 पहुंचा। आवाज और स्किन से वह जवान लग रहा था। शक होने पर सीआईएसएफ ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ की। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रशवेंद्र सिंह बताया, जिसका जन्म 10 फरवरी, 1957 को हुआ था। उसने बताया कि वह रात 10:50 बजे एयर कनाडा की फ्लाइट से कनाडा जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया, उसकी शकल, आवाज और स्किन पासपोर्ट में दी गई डिटेल्स से काफी कम उम्र की लग रही थी। करीब से देखने पर पता चला कि उसने अपने बाल और दाढ़ी सफेद की हुई थी और बूढ़ा दिखने के लिए एयरबेस भी पहना हुआ था। 18 जून को शाम 5:20 बजे सीआईएसएफ स्टाफ ने टर्मिनल 3 के चेक-इन एरिया में उसे रोका। पूछताछ के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया पकड़े गए युवक ने पूछताछ

में बताया कि उसकी असली उम्र 24 साल और नाम गुरुसेवक है। उसने खुलासा किया कि वह और उसकी पत्नी बेहतर आजीविका के लिए अमेरिका जाना चाहते थे और वह एक दोस्त के जरिए से एजेंट जगजीत के संपर्क में आया। युवक ने अधिकारी को बताया, एजेंट ने हमें 60 लाख रुपये के बदले किसी और के पासपोर्ट का इस्तेमाल करके कनाडा से अवैध तरीके से अमेरिका भेजने का वादा किया। हमने उसे 30 लाख रुपये दिए और यह तय हुआ कि बाकी की रकम डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद दी जाएगी। डीसीपी (आईजीआई) उषा रंगनानी ने बताया कि एजेंट ने उसके लिए रशवेंद्र सिंह नाम से पासपोर्ट और उसकी पत्नी अर्चना कौर के लिए हरजीत कौर के नाम से कनाडा जाने के लिए दूसरा पासपोर्ट बनवाया। उन्होंने बताया, जगजीत के निर्देश पर उसका एक साथी उसे तिलक नगर के एक सैलून में ले गया, ताकि वह पासपोर्ट धारक की उम्र से मिलता-जुलता बूढ़ा आदमी बन सके। सैलून के एक कर्मचारी ने उसका पासपोर्ट फोटो जैसा दिखने के लिए मेकअप किया। पुलिस अधिकारी ने कहा, जगजीत ने कनाडा की यात्रा के लिए टिकट का इंतजाम भी कर दिया, लेकिन गुरुसेवक को शक के आधार पर एयरपोर्ट स्टाफ ने पकड़ लिया। उसकी पत्नी को भी एयरपोर्ट के पास से पकड़ गया, क्योंकि वह फनी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश कर रही थी।

खत्म होगा खेड़की दौला टोल प्लाजा, नए सिस्टम से कटेगा टैक्स; गडकरी ने बताया प्लान

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर गुरुग्राम और रेवाड़ी जिले की विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। राव इंद्रजीत ने गडकरी के सामने खेड़की दौला टोल का मुद्दा भी उठाया। नितिन गडकरी ने कहा कि सेटोलाइट सिस्टम शुरू होने के बाद खेड़की दौला टोल खत्म हो जाएगा। इस काम में दो महीने का समय और लगेगा। गडकरी ने कहा कि इससे वाहन चालक जहां से हवाई पर प्रवेश करेगा, वहां से उसकी एंटी दर्ज होगी। निकास के समय किलोमीटर के हिसाब से

ऑटोमेटिक टोल कट जाएगा। दिल्ली-जयपुर हवाई पर टोल कलेक्शन की नई प्रणाली लागू होगी। बैटक में हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वी उमाशंकर, गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे। राव इंद्रजीत ने गडकरी के समक्ष हीरो हॉंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक एलीवेटेड रोड के निर्माण की मांग को दोहराया। वी उमाशंकर ने उपायुक्त की मौजूदगी में इस राष्ट्रीय राजमार्ग का मामला उठाया। नेशनल हवाई के अधिकारियों ने बताया कि इस रूट में मेट्रो भी गुजर रही है, जिससे तकनीकी अडिचनें आ रही हैं। राव ने बिलासपुर चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण धीमी



गति से होने की भी बात रखी। उन्होंने बताया कि यहां लोगों को भारी परेशानी हो रही है। गडकरी ने एनएचआई के अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। राव इंद्रजीत ने गडकरी से राठीवास मोड़, साल्हावास मोड़, पचागांव चौक पर अंडरपास का निर्माण भी जल्द शुरू कराने की अनुरोध किया। इस पर गडकरी ने एनएचआई के अधिकारियों से दोनों परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तलब की। अधिकारियों ने बताया कि इस माह के अंत तक अंडरपास की टेंडर प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। बैटक में गुडगांव-पटौदी-रेवाड़ी हवाई को लेकर भी चर्चा हुई। नैल्सन मंडेला मार्ग को

संक्षिप्त समाचार

मैच के दौरान  
बैडमिंटन खिलाड़ी  
की मौत

इंडोनेशिया में अंतरराष्ट्रीय  
टूर्नामेंट के दौरान आया हार्ट  
अटैक



नई दिल्ली, एजेंसी। इंडोनेशिया में एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के दौरान कोर्ट पर गिरने से 17 वर्षीय चीनी बैडमिंटन खिलाड़ी की मौत हो गई। खिलाड़ी का नाम झांग झिजी है जिसकी बैडमिंटन कोर्ट में हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं इस घटना पर भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने भी सोशल मीडिया भी दुखी नजर आई। यह घटना रविवार देर रात को है। झांग झिजी ने किंडरगार्टन में बैडमिंटन खेलना शुरू किया और पिछले साल उन्हें चीन की नेशनल यूथ टीम में शामिल किया गया। इंडोनेशिया (जकार्ता) में एक टूर्नामेंट के दौरान कोर्ट पर चीनी बैडमिंटन खिलाड़ी पहले बेहोश हुआ और फिर उसे हार्ट अटैक आया जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में झांग झिजी को वेन्यू पर ही इलाज दिया गया लेकिन हलचल न दिखते हुए फिर उनको एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रात में उनकी मौत हो गई।

पीवी सिंधु ने जताया शोक

इस खिलाड़ी की मौत के बाद भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने एक पोस्ट लिखा है। सिंधु ने पर लिखा- जुनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप से युवा बैडमिंटन खिलाड़ी झांग झिजी के निधन की खबर बेहद दुख है, मैं इस दुखद समय में झांग के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। आज दुनिया ने एक असाधारण प्रतिभा खो दी है।

रोनाल्डो ने अपने  
रिटायरमेंट को लेकर  
किया बड़ा ऐलान

नई दिल्ली, एजेंसी। बात अगर फुटबॉल की हो, और रонаल्डो का नाम न आए ऐसा हो नहीं सकता। फुटबॉल के मैदान में अपना जादू बिखारने वाले क्रिस्टियानो रонаल्डो किसी न किसी खबर से घिरे ही रहते हैं। लेकिन इस बार उनकी चर्चा होने की वजह उनका फुटबॉल से संन्यास है।

जी हाँ, पुर्तगाल के फुटबॉल जांबाज क्रिस्टियानो रонаल्डो यूरो कप से संन्यास ले रहे हैं और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है। रонаल्डो ने कहा है कि इस बार वो अपना आखिरी यूरो कप खेल रहे हैं और फिर इसके बाद वो यूरोपियन चैंपियनशिप में नहीं खेलेंगे।

रोनाल्डो का फुटबॉल से  
संन्यास

आपको बता दें कि 2024 का यूरो कप जर्मनी में खेला जाने वाला है। जिसमें रонаल्डो की टीम (पुर्तगाल) ने स्लोवेनिया को हरा दिया है। ऐसे में अब टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है और अब उनका मुकाबला फ्रांस की टीम के साथ होने वाला है। इस मैच में रонаल्डो की आंखों से तब आंसू टपक गए, जब उन्होंने स्लोवेनिया के खिलाफ पेनल्टी मिस कर दी। उनको भावुक होता देख उनकी मां की आंखों से भी आंसू छलक गए। इस मैच के बाद ही रонаल्डो ने इस बात की जानकारी एक पुर्तगाली चैनल के माध्यम से दी कि ये उनका आखिरी यूरो मैच है।

हॉकी

पहली बार होने वाले इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा हॉकी इंडिया

40 से अधिक उम्र के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा



नई दिल्ली, एजेंसी। हॉकी इंडिया से संबद्ध सभी राज्य सदस्य इकाइयां इस आयोजन में भाग लेने के लिए पात्र हैं। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के इच्छुक 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र खिलाड़ियों को अपनी संबंधित सदस्य इकाइयों से संपर्क करना होगा। हॉकी इंडिया 40 साल से अधिक उम्र के पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए होने वाले मास्टर्स कप टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। यह पहली बार है जब हॉकी इंडिया इस टूर्नामेंट की

मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट का मकसद अनुभवी हॉकी खिलाड़ियों के जुनून और कौशल का जश्न मनाने का है। टूर्नामेंट की तारीखों और स्थल की घोषणा बाद में की जाएगी। हॉकी इंडिया से संबद्ध सभी राज्य सदस्य इकाइयां इस आयोजन में भाग लेने के लिए पात्र हैं। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के इच्छुक 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र खिलाड़ियों को अपनी संबंधित सदस्य इकाइयों से संपर्क करना होगा। इन खिलाड़ियों को हॉकी

इंडिया की सदस्य इकाई की वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिकी ने कहा, हम पहली बार हॉकी इंडिया मास्टर्स कप की घोषणा करते हुए रोमांचित हैं। यह ऐसा आयोजन होगा जो हमारे अनुभवी खिलाड़ियों के सम्पन्न और जुनून को मान्यता देगा। यह टूर्नामेंट खेल के प्रति उनके स्थायी प्रेम के जश्न के साथ हॉकी में उनके अमूल्य योगदान का एक प्रमाण है।

टोक्यो ओलंपिक समाप्त होते ही मैंने पेरिस 2024 के लिए तैयारी शुरू कर दी थी: निखत जरीन



नई दिल्ली, एजेंसी। निखत जरीन पेरिस 2024 में अपने प्रभावशाली पदक संग्रह को बढ़ाने के लिए ओलंपिक पदक पर नजर रख रही हैं। छह भारतीय मुक्केबाज, चार महिलाएं और दो पुरुष, ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है और उनमें से पांच खेलों के लिए फ्रांस की राजधानी जाने से पहले 22 जुलाई तक जर्मनी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। टीम में निखत जरीन (महिला 50 किग्रा), प्रीति पवार (महिला 54 किग्रा), टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोगोहेन (महिला 75 किग्रा), निशांत देव (पुरुष 71 किग्रा) और अमित पंचल (पुरुष 51 किग्रा) शामिल हैं। टोक्यो 2020 में भारत का अभियान समाप्त होने के बाद से, जरीन का ध्यान पेरिस 2024 पर केंद्रित है, उन्हें विश्वास है कि यह उनके लिए अपनी चमक दिखाने का क्षण है। जरीन ने जियोसिमेना से कहा

कि जब टोक्यो ओलंपिक में भारत का अभियान समाप्त हुआ, तो उस दिन मैंने अपना ध्यान पेरिस ओलंपिक की तैयारी में लगाने का फैसला किया। मैंने पेरिस की उलटी गिनती के बारे में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी पोस्ट की। मुझे लगता है कि हर किसी का अपना एक पल होता है, और यह मेरा पल है। जिसने भी कहा था कि मैं पेरिस नहीं पहुंच पाऊंगी, मैंने आखिरकार इसे हासिल कर लिया। मैं अपने आस-पास की सभी नकारात्मकता और सकारात्मकता को सकारात्मक रूप से लुंगी और पेरिस में रिंग के अंदर एक अलग फाइटर के रूप में बेहतर होने की कोशिश करूंगी। अपनी सफलता की राह पर विचार करते हुए, जरीन अपने समुदाय में सामाजिक मानदंडों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता के अटूट समर्थन को देती हैं। मेरी यात्रा उतार-चढ़ाव भरी रही है, मैं एक ऐसे

समुदाय से आती हूँ जहां महिलाओं को समर्थन की कमी है। लेकिन मेरे पिता, जो खुद एक एथलीट हैं, जानते थे कि एक चैंपियन बनने के लिए क्या करना पड़ता है। उन्होंने हमेशा मेरी यात्रा में मेरा समर्थन किया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपना ध्यान बॉक्सिंग पर केंद्रित करना चाहिए। जब आप देश के लिए मेडल जीतने का सपना पूरा कर लेंगे, उस दिन ये लोग आपको बधाई देने आएंगे और सेल्फी लेंगे। जरीन ओलंपिक चैंपियन बनने की अनूठी चुनौती को रेखांकित करते हुए, अपने खेल के शिखर तक पहुंचने के लिए आवश्यक बलिदानों पर जोर देती हैं। मैंने विषय चैंपियन बनने के लिए कई चीजों का त्याग किया है, लेकिन ओलंपिक चैंपियन बनना अलग बात है। जब भी मैं प्रतिযোগिताओं की तैयारी कर रही होती हूँ, मैं सोशल मीडिया से दूर रहती हूँ।

मैं अपने परिवार या दोस्तों के साथ ज्यादा बात नहीं करती हूँ। मैं उनके साथ समय बिताती हूँ। इस बार, पेरिस 2024 की तैयारी में, मैं इन सभी विकल्पों से दूर रहने की कोशिश करूंगी, और जितना संभव हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करूंगी और पेरिस के लिए कोई कदम नहीं छोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। पदक से पहले की हर जंग से पहले की अपनी मानसिकता की झलक दिखाते हुए जरीन ने हर मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के महत्व पर जोर दिया। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने के मकसद से उतरती हूँ ताकि रिंग के अंदर चाहे कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, मुझे इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने 10 प्रतिशत और दिया होता तो मैं मुकाबला जीत सकती थी। मैं वह पछतावा नहीं चाहती, इसलिए मैं हमेशा अपना 100 प्रतिशत देने की मानसिकता के साथ उतरती हूँ। निखत जरीन के शानदार करियर में यह विषय चैंपियनशिप स्वर्ण पदक, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में एक स्वर्ण और 2022 एशियाई खेलों में एक कांस्य पदक शामिल हैं। वह उन छह भारतीय मुक्केबाजों में शामिल हैं, जिन्होंने महिलाओं के 50 किग्रा वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए पेरिस 2024 के लिए क्वालीफाई किया है।

विमलडन :

गत चैंपियन मार्केटा  
वॉद्रोसोवा उलटफेर का  
शिकार हुई



लंदन, एजेंसी। महिला सिंगल्स विमलडन की गत चैंपियन टीम का वर्ग में पिछले साल की विजेता 25 वर्षीय वॉद्रोसोवा को वर्ग के तीसरे ग्रैंडस्लैम में गैर वरीयता प्राप्त जैसिका बोउजास मानेरिओ से एक घंटा सात मिनट तक चले मुकाबले में लगातार सेटों में 4-6, 2-6 से हार का सामना करना पड़ा। गत चैंपियन मार्केटा वॉद्रोसोवा का विमलडन का बचाव का अभियान विमलडन के पहले ही दौर में हार के साथ समाप्त हो गया। महिला सिंगल्स वर्ग में पिछले साल की विजेता 25 वर्षीय वॉद्रोसोवा को वर्ग के तीसरे ग्रैंडस्लैम में गैर वरीयता प्राप्त जैसिका बोउजास मानेरिओ से एक घंटा सात मिनट तक चले मुकाबले में लगातार सेटों में 4-6, 2-6 से हार का सामना करना पड़ा। महिलाओं के वर्ग में टूर्नामेंट में यह पहला बड़ा उलटफेर है। जैसिका पहली बार किसी ग्रैंडस्लैम के मुख्य दौर में पहुंची थीं और उन्होंने गत चैंपियन खिलाड़ी को उलटफेर का शिकार बनाकर अपना प्रभाव छोड़ा। 1994 में स्टेपी ग्राफ के पहले दौर में बाहर होने के बाद यह पहली बार है जब

विमलडन की गत चैंपियन टीम का सफर शुरुआती दौर में ही समाप्त हुआ है। वॉद्रोसोवा पहले ही राउंड में संघर्ष करती दिखाईं और उन्होंने 28 बेजॉ भूलें की। हारने के बाद वॉद्रोसोवा काफी निराश दिखाईं और मैच के बाद जैसिका से हाथ मिलाने के दौरान उनके चेहरे पर इस हार का दुख साफ झलक रहा था। दूसरी तरफ जैसिका अपनी इस उपलब्धि का जश्न मनाने से खुद को नहीं रोक सकीं और टेनिस कोर्ट पर ही उछल पड़ीं। वॉद्रोसोवा ने मैच में सात डबल फॉल्ट किए, वहीं जैसिका ने गत चैंपियन खिलाड़ी की पांच बार सर्विस तोड़ी और मुकाबले को एकतरफा बना दिया। जैसिका ने मैच के बाद कहा, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि यह मेरे जीवन और करियर के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। मैं बस एक बेहतरीन महिला सिंगल्स खिलाड़ी के खिलाफ खेलने के दौरान उस पल का आनंद लेने के बारे में सोच रही थी। उन्होंने पिछले साल यहां खिताब जीता था। मैं सोच रही थी कि मुझे पर कोई दबाव नहीं है और मैं आनंद लेना चाहती हूँ।

फैंस का दिल टूट गया...

मेसी ओलंपिक नहीं खेल पाएंगे

ब्यूनस आयर्स, एजेंसी। लियोनेल मेसी इस महीने के अंत में पेरिस में शुरू होने वाले ओलंपिक में अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम का हिस्सा नहीं होंगे। कोच जेवियर माशेरानो ने मंगलवार को घोषित टीम में विश्व कप विजेता टीम के चार सदस्यों को जगह दी जिसमें स्ट्राइकर जूलियन अल्वारैज और डिफेंडर निकोलस ओटांमेंडी शामिल हैं। इस साल चोटों से जूझ रहे 37 वर्षीय मेसी अभी कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। टीम का लक्ष्य 2021 में जीते गए महाद्वीपीय खिताब का बचाव करना है। अर्जेंटीना ने

2021 में कोपा अमेरिका जीतने के बाद 2022 में विश्व कप भी जीता था। मेसी ने अपने एकमात्र ओलंपिक अभियान में 2008 में बीजिंग में टीम पदक जीतने वाले माशेरानो कोपा अमेरिका खत्म होने के बाद गोलकीपर गेरॉनिमो रुली, ओटांमेंडी और अल्वारैज को टीम में शामिल करेंगे। हाल ही में रिवर प्लेट से मैनचेस्टर सिटी में शामिल हुए मिडफील्डर क्लॉडियो एचेवेरी भी टीम में शामिल होंगे। अर्जेंटीना 24 जुलाई को मोरक्को के खिलाफ ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट के अपने पहले मैच से पूर्व फ्रांस में दो मैत्री मैच खेलेगा। अर्जेंटीना और मोरक्को के अलावा इराक और यूक्रेन को ग्रुप बी में जगह मिली है।

प्रत्येक टीम में तीन अधिक उम्र के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति दी जाती है। वर्ष 2004 और 2008 में खिलाड़ी के तौर पर ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले माशेरानो कोपा अमेरिका खत्म होने के बाद गोलकीपर गेरॉनिमो रुली, ओटांमेंडी और अल्वारैज को टीम में शामिल करेंगे। हाल ही में रिवर प्लेट से मैनचेस्टर सिटी में शामिल हुए मिडफील्डर क्लॉडियो एचेवेरी भी टीम में शामिल होंगे। अर्जेंटीना 24 जुलाई को मोरक्को के खिलाफ ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट के अपने पहले मैच से पूर्व फ्रांस में दो मैत्री मैच खेलेगा। अर्जेंटीना और मोरक्को के अलावा इराक और यूक्रेन को ग्रुप बी में जगह मिली है।



डेविड मिलर ने ले  
लिया संन्यास?

अब सामने आकर कही ये बात

नई दिल्ली, एजेंसी। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम की जीत, विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बीच सूर्यकुमार यादव का ऐतिहासिक कैच भी काफी चर्चाओं में रहा है। यह कैच मुकाबले के आखिरी ओवर की पहली बॉल पर आया था। इस कैच के कारण डेविड मिलर पवेलियन लौटे थे और साउथ अफ्रीका के साथ से खिताब जीतने का मौका फिसल गया था। इन सभी के बाद एक खबर और आई थी कि मिलर मिलर कहे जाने वाले इस अफ्रीकी स्टार ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऐसे में फाइनल हार से निराश अफ्रीकी फैंस को और भी



ज्यादा झटका लगा था। मगर अब मिलर ने खुद आकर इस बात पर सफाई दी है। दरअसल, डेविड मिलर ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है, जिसके जरिए कहा है कि उनके टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की जो खबरें चल रही हैं, वो बेवुनियाद हैं। यह सब अफवाह है।

डीएफसी ने  
क्वार्टर फाइनल  
में किया प्रवेश

चंडीगढ़, एजेंसी। कौशल और दृढ़ संकल्प के शानदार प्रदर्शन के साथ पहले चैंपियन डीएफसी ने एआईएफएफ फुटसल क्लब चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। उन्होंने अपने अंतिम ग्रुप चरण के मैच में मध्य प्रदेश के चैंपियन कासा बरवानी के शानदार जीत के बाद यह उपलब्धि हासिल की। मैच की शुरुआत पौड के शानदार प्रदर्शन से हुई, जिसकी व्यक्तिगत प्रतिभा ने डीएफसी को शुरुआत में ही स्कोरबोर्ड पर पहुंचा दिया। किपेन ने पेनल्टी को गोल में बदलकर बढ़त को बड़ा करते हुए दबाव में अपनी सटीकता और धैर्य का परिचय दिया। कासा बरवानी के अबुजाफर ने एक गोल करके वापसी की और पहले हाफ का अंत 2-1 स्कोर से किया। हालांकि, दूसरे हाफ में डीएफसी के युवा सर्वारियर्स ने शानदार प्रदर्शन किया और पहले मिनट से ही मैदान पर अपना दबदबा बना लिया। थियाम और लुकिम ने दो तेज गोल करके बढ़त को और आगे बढ़ाया।

शेर-ए-पंजाब टी-20 कप का दूसरा सीजन सफल

मोहाली, एजेंसी। शेर-ए-पंजाब टी-20 कप के दूसरे सीजन में रोमांचक क्रिकेट देखने को मिला, जिसने धीरे-धीरे सीजन की शानदार शुरुआत की। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) द्वारा आयोजित टी-20 लीग में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, जिसमें रोमांचक अंत देखने को मिला। बीएलवी ब्लास्टर्स और ट्राइडेंट स्टैलिऑन के बीच खेला गया फाइनल इस टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मैच रहा, जिसमें नमन धीर की अगुआई वाली टीम ब्लास्टर्स ने मोहाली के आईएस बिंद्रा पीसीए क्रिकेट स्टेडियम में लगातार दूसरे सीजन का खिताब अपने

नाम किया। बीएलवी ब्लास्टर्स के ओपनिंग बल्लेबाज हरनूर पत्र ने शेर-ए-पंजाब टी 20 कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया। 21 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ने न केवल 52 गेंदों में 83 रनों की मैच विजयी पारी खेली और अपनी टीम को खिताब दिलाया। 12 मैचों में 578 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने, जिसमें उन्होंने कुल 33 मैचों के टूर्नामेंट में 33 छक्के लगाए। यह हरनूर के लिए एक आदर्श घर वापसी साबित हुई, जिन्होंने पंजाब के लिए अपना अंडर-14 और अंडर-16 क्रिकेट खेला, लेकिन 2019 में चंडीगढ़ यूनिट को बीसीसीआई से संबद्धता मिलने पर वे

बल्लेबाजों ने लगाए 868 चौके और 460 छक्के



यूटी क्रिकेट एसोसिएशन में चले गए। वेस्टइंडीज में अंडर-19 विश्व कप पहले एशिया कप और फिर 2022 में जीतने वाली भारतीय अंडर-19 टीम का

हिस्सा रहे हरनूर अपने करियर को पुनर्जीवित करने के लिए 2024 में फिर से पंजाब लौट आए। 2021 में अंडर-19 एशिया कप के दौरान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हरनूर ही नहीं, कार्तिक शर्मा (457 रन), प्रभासिम्पन सिंह (454 रन), अभय चौधरी (445 रन), पुष्पराज कप (334 रन) जैसे अन्य बल्लेबाजों ने भी अपनी बल्लेबाजी प्रतिभा से प्रभावित किया। अनुभवी मंदीप सिंह ने भी एपी किंग्स नाइट्स के लिए खेलते हुए 349 रन बनाए। गेंदबाजी में, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने गेंद के साथ अपनी क्लास और आक्रामकता दिखाई।

ट्राइडेंट स्टैलिऑन के लिए खेलते हुए 11 मैचों में उनके 22 विकेट के साथ उनके कौशल को दर्शाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शीर्ष पांच गेंदबाजों में 2 मध्यम गति के गेंदबाज और 3 स्पिनर शामिल हैं। इसमें से एक हरप्रीत बरार ने फाइनल में आखिरी ओवर में 4 गेंदों पर 12 रन बनाकर ब्लास्टर्स को जीत दिलाई। मध्यम गति के गेंदबाज आराधु शुक्ला, जो 2023 में भारत की अंडर-19 विश्व कप टीम का हिस्सा थे, उन्होंने भी ब्लास्टर्स के लिए 16 विकेट लेकर गेंद से प्रभावित किया।

# ग्राम पंचायतों की जनसुनवाई में आए 724 आवेदन

## ग्रामवासियों की समस्याओं का हुआ त्वरित निराकरण



पन्ना। कलेक्टर सुरेश कुमार के निर्देशानुसार एवं शासन की मंशानुरूप सुशासन के जरिए आमजनों की समस्याओं के तत्काल निराकरण और ग्रामवासियों की सुविधा के दृष्टिगत प्रत्येक मंगलवार को जिले के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर जनसुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आज सम्पन्न हुई जनसुनवाई में जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में कुल 724 आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान ग्रामवासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया गया है।

जनपद पंचायत गुनौर अंतर्गत सभी 80 ग्राम पंचायतों में सम्पन्न हुई जनसुनवाई में कुल प्राप्त 255 आवेदनों में से 221 का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष 34 आवेदन पत्रों में कार्यवाही प्रचलन में है। इसी तरह अजयगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में प्राप्त 99 आवेदनों में से 97 आवेदनों पर कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। पन्ना जनपद

पंचायत की समस्त ग्राम पंचायतों में प्राप्त 139 आवेदनों में से 119 पर तथा पर्वी जनपद पंचायत की समस्त ग्राम पंचायत में प्राप्त 114 आवेदनों में से 107 आवेदनों का तत्काल निराकरण किया गया, जबकि शाहनगर की समस्त ग्राम पंचायतों में प्राप्त 117 में से 94 आवेदनों का निराकरण किया गया। ग्राम पंचायत की जनसुनवाई

में पंचायत सचिव और रोजगार सहायक सहित समस्त मैदानों कर्मचारी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर द्वारा जिले के दूरस्थ क्षेत्रों से जिला मुख्यालय की जनसुनवाई में आने वाले गरीब व्यक्तियों की दिक्कतों के मद्देनजर सभी ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई आयोजन के निर्देश जारी किए गए थे। साथ

ही मॉनिटरिंग के लिए पर्यवेक्षण अधिकारियों की इयूटी तय कर संबंधित विभाग के मैदानों कर्मचारियों को सुबह 11 से 1 बजे तक ग्राम पंचायत में अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया गया था। इस क्रम में आज ग्राम पंचायत मुख्यालयों में सम्पन्न हुई जनसुनवाई में उपस्थित लोकसेवकों द्वारा

ग्रामीणजनों के आवेदन प्राप्त कर समस्या निराकरण की त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की गई। इससे आवेदकों की समस्याओं का शीघ्र एवं आसानी से निराकरण हुआ। साथ ही ग्राम पंचायत अथवा विकासखण्ड स्तर की शिकायत और समस्याओं के निराकरण के लिए पन्ना जिला मुख्यालय तक आवागमन नहीं करना पड़ा। प्रत्येक मंगलवार को ग्रामीणजनों द्वारा ग्राम पंचायत की जनसुनवाई में उपस्थित होकर समस्या का समाधान कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में 31 आवेदन प्राप्त हुए। यहाँ भी अधिकारियों द्वारा आम लोगों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को तत्परता से निराकरण के निर्देश दिए गए। सभी 9 तहसीलों में संबंधित तहसीलदार द्वारा भी जनसुनवाई की गई।

## कलेक्टर में वाटर कूलर का शुभारंभ



पन्ना। प्राणनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा कलेक्टर परिसर में आने वाले आगंतुकों सहित लोकसेवकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाटर कूलर स्थापित करवाया गया है। इससे लोगों को आसानी से शुद्ध व शीतल पेयजल मिल सकेगा। कलेक्टर सुरेश कुमार द्वारा आज वाटर कूलर का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्र, संयुक्त कलेक्टर के.एस. गौतम सहित प्राणनाथ मंदिर के उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा, न्यासी चन्द्र किशन त्रिपाठी, प्रबंधक आशीष शर्मा एवं धामी समाज के उपाध्यक्ष बालकृष्ण शर्मा भी उपस्थित रहे।

## लगातार आवेदन देने के बावजूद ठेकेदार पर नही हो रही कार्यवाही

### विधायक ने भी कलेक्टर से कार्यवाही करने लिखा पत्र

पन्ना। जिले के शाहनगर तहसील मुख्यालय में ठेकेदार अनूप सिंह द्वारा पेटी ठेकेदार संभू शिवहरे के माध्यम से ग्राम पंचायत शाहनगर में पिपरिया तालाब की अवैध रूप से खोदाई कराई गई तथा उक्त तालाब की मुरुम एवं मिट्टी को आई टी आई परिषद में लगाया गया। मशीनों के खोदाई के कारण पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा तालाब में कराये गये निर्माण कार्य को नष्ट किया गया है। जिसको लेकर शाहनगर ग्राम पंचायत के सरपंच मनोज जैन द्वारा अनेको बार जिला कलेक्टर तथा अन्य अधिकारियों को पत्र देकर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग भी की गई है। दिये गये आवेदन में क्षेत्रीय विधायक प्रहलाद लोधी द्वारा भी जिला कलेक्टर को अनुरोध करते हुए तत्काल ठेकेदार के खिलाफ अवैध उत्खनन एवं वसूली प्रकरण दर्ज

कराने का अनुरोध किया गया है। आवेदन में बताया गया कि उक्त तालाब मनरेगा योजना के तहत चाल लाख 97 हजार के विरुद्ध तीन लाख 68 हजार की राशि से गहरा कराया गया था। जिसको नष्ट किया गया है। भू राजस्व अंतर्गत अवैध रूप से नष्ट किये गये तालाब में नियम अनुसार 4 गुना अर्थ दण्ड लगाने का प्रावधान है। जिसमें 14 लाख 72 हजार की राशि ठेकेदार से वसूली करने का नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया था। लेकिन ठेकेदार ने आज दिनांक तक कोई जवाब नहीं दिया है। बेतरतीब ढंग से की गई खोदाई से तालाब में बड़े बड़े गड्ढे हो गये हैं। जिससे आये दिन पशुओं एवं अन्य जीवों के गिरने की प्रबल संभावना है। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि संबंधित के खिलाफ गोडू खनिज अधिनियम 1996 संशोधित 2013 के अंतर्गत पंचायत को राशि दिलाई जाये तथा बिना अनुमति के ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य पर दण्डनीय अपराध दर्ज कर कार्यवाही की जाये।

## यातायात प्रभारी ने पकड़े रेत से भरे बिना नम्बर के ट्रैक्टर, सैतालीस हजार का किया चालान

पन्ना। पन्ना जिला मुख्यालय में इन दिनों रेत से भरे ट्रैक्टर लगातार धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। उक्त ट्रैक्टर चालक सकरी कुलियों से भी स्पीड से दौड़ते हैं। जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है, अनेक चौराहों पर ट्रैक्टर चालक रेत बेचने के लिए मजमा लगाये देखे जा सकते हैं। उक्त ट्रैक्टरों में नम्बर भी नहीं डाले गये हैं। जिससे दुर्घटना करने के बाद संबंधितों के खिलाफ



कार्यवाही की जाये। लेकिन अनेको बार खनिज विभाग को भी अवगत कराया गया। लेकिन उसके बावजूद कोई कार्यवाही यातायात थाना प्रभारी द्वारा उक्त बिना नम्बरों के नौ ट्रैक्टरों के खिलाफ चालान

## उपचार के लिए राशि की स्वीकृति

पन्ना। कलेक्टर सुरेश कुमार ने गुनौर विधायक राजेश कुमार वर्मा की अनुरोध पर विधायक स्वच्छानुदान निधि के तहत जारी निर्देशानुसार तीन हितग्राहियों को उपचार के लिए राशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। अमानगंज तहसील के हरदाही निवासी लखन पटेल एवं दूरी निवासी वंदना कुशवाहा के इलाज के लिए दस-दस हजार रूपए और गुनौर तहसील के ग्राम पट्टेरी निवासी पूनम कुशवाहा के इलाज के लिए पांच हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।

## ग्राम पंचायत की जनसुनवाई में ग्रामीणों का दिखा उत्साह

केवायसी के प्रकरण का हुआ निपटारा, ग्रामीणों ने कहा समय और पैसा दोनों की होगी बचत

पन्ना। जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार की पहल से मंगलवार के दिन जनसुनवाई का आयोजन किया जाता रहा है। अब यह जन सुनवाई ग्राम पंचायत स्तर पर भी की जायेगी। इसी कड़ी में पहले मंगलवार को जनपद पंचायत अजयगढ़ की 65 ग्राम पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मागदर्शन में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया। समर्थन संस्था ने भी 30 ग्राम पंचायत में 60 पंचायत मित्रों को सामाजिक सुरक्षा



में आ रही समस्या को दूर करने में पंचायत को सहयोग करने एवं सामुदाय को जानकारी देने में सहयोग किया गया। जनपद की सभी ग्राम पंचायत में जनसुनवाई के प्रति उत्साह देखा गया एवं जर्मनी अमला पूरे सतय तैनात रहा। जनपद स्तर की नॉडल टीम भी ग्राम पंचायतों में जाकर सहयोग

किया। ग्राम पंचायत राजपुर के सचिव मिठाईलाल, सहायक सचिव बाबू सिंह राजपूत एवं दिलीप अहिरवार ने हितग्राहियों को मदद की। ग्राम पंचायत राजपुर एवं नन्दनपुर में नवल किशोर पटेल पंचायत समन्वय अधिकारी ने जाकर देखा एवं टीम का उत्साह बर्धन किया और कहा की जनता को पंचायत में ही सभी सुविधा मिले इसके लिये हम सब मिलकर काम करेंगे। किसी पात्र परिवार को जनपद एवं जिले में न आना पड़े इसके लिये सरकार ने मंगलवार

को ग्राम पंचायत में जनसुनवाई रखी है ताकि लोगों को गांव में ही सुविधा मिल सके। जनसुनवाई की सराहना-पंचायत में आये लोगों ने कहा की छोटी-छोटी समस्याओं के लिये जिला मुख्यालय तक भागना पड़ता था जिससे अब निजात मिलेगी तथा समय एवं पैसा की बचत होगी। समर्थन संस्था के क्षेत्रीय समन्वयक 'ज्ञानेन्द्र तिवारी ने कहा की कलेक्टर सुरेश कुमार की यह पहल जन हितैषी है। इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।

## श्रमिक पंजीयन तथा योजनाओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य

पन्ना। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में पारदर्शिता के लिए निर्माण श्रमिक पंजीयन तथा योजनाओं के आवेदन के समय ई-केवाईसी व योजना अंतर्गत हितलाभ वितरण आधार आधारित भुगतान प्रक्रिया के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। पंजीकृत श्रमिक-हितग्राही की आधार ई-केवाईसी करिये जाने के पश्चात ही किसी भी योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। पंजीकृत श्रमिक व हितग्राही के बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य है।

## लोकपथ मोबाइल ऐप लांच

पन्ना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज लोक निर्माण विभाग के लोकपथ मोबाइल ऐप को लांच किया। इसके जरिए सड़कों का आवश्यकतानुसार त्वरित रूप से सुधार संभव होगा। लोकपथ मोबाइल ऐप सड़क सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मोबाइल ऐप से आमजन को मार्गों की समस्या बताने की सुविधा मिलेगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। लोकपथ मोबाइल ऐप को लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर इंस्टॉल किया जा सकता है। मोबाइल फोन में ऐप को खोलकर ऐप में

## सात दिन में होगा सड़कों में सुधार

रजिस्टर्ड सड़कों का फोटो लेकर डालने पर शिकायत निराकरण के लिए सीधे संबंधित अधिकारी को पहुंच जाएगा। अधिकारी द्वारा सात दिवस की समय सीमा में स्पॉट होल-पेच का सुधार कार्य कर ऐप से निराकरण दर्ज किया जाएगा, जिसकी सूचना मोबाइल पर शिकायतकर्ता को प्राप्त हो जाएगी। लोक निर्माण विभाग के अधीन प्रदेश के समस्त मरम्मत योग्य राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला एवं अन्य जिला व ग्रामीण मार्ग सम्मिलित रहेंगे। यह योजना दो चरणों में लागू की जाएगी। प्रथम चरण मंगलवार, 2 जुलाई से आरंभ किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और मुख्य जिला मार्ग शामिल रहेंगे। द्वितीय चरण में प्रथम चरण में सम्मिलित मार्गों के साथ शेष अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्गों को शामिल किया जाएगा।

## तहसील मुख्यालयों पर भी हुई जनसुनवाई

पन्ना। मंगलवार को जिले की सभी 9 तहसील मुख्यालयों पर भी जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान संबंधित तहसीलदार द्वारा कुल प्राप्त 45 आवेदनों पर निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। सर्वाधिक 18 आवेदन अजयगढ़ तहसील में प्राप्त हुए, जबकि रेणुपुर तहसील में मात्र 1 आवेदन प्राप्त हुआ। गुनौर तहसील में 5 आवेदन, पर्वी, सिमरिया, देवेन्द्रनगर और शाहनगर तहसील में 4-4, अमानगंज तहसील में 3 आवेदन और पन्ना तहसील में 2 आवेदन प्राप्त हुए।

## नवीन वार्डों में पोषण आहार प्रदाय के लिए प्रस्ताव आमंत्रित

पन्ना। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद पन्ना के नवीन 6 वार्डों में 03 से 06 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषण आहार प्रदाय करने के लिए महिला स्वसहायता समूहों के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। वार्ड क्र. 23 से 28 के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राज्य शहरी आजीविका मिशन और तेजस्वनी कार्यक्रम के क्रियाशील इच्छुक स्थानीय महिला स्वसहायता समूह 3 से 13 जुलाई तक प्रस्ताव जमा कर सकते हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय संयुक्त कलेक्टर भवन पन्ना से प्रस्ताव प्रारूप और दिशा निर्देश प्राप्त कर कार्यालयीन समय में जमा कराया जा सकता है।

## एलोपैथी, होम्योपैथी के साथ चिकित्सकों की सिंपैथी की जरूरत है: बहन जी

पन्ना। अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के उपलक्ष में ब्रह्माकुमारी विद्यालय पन्ना की ओर से स्वास्थ्य केंद्र देवेन्द्रनगर में डॉक्टर्स के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ वृक्षारोपण के साथ किया गया। बहन जी ने सभी डॉक्टरों का सम्मान करते हुए एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। आप पर परिवार के साथ-साथ समाज की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, डॉक्टर का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम देखते हैं कि 90 प्रतिशत बीमारी मन के कमजोर होने से उत्पन्न होती है, मरीज को आधी से ज्यादा बीमारी डॉक्टर के स्नेहपूर्ण व्यवहार से ठीक हो जाती है तो



डॉक्टर का तन को स्वस्थ रखने के साथ-साथ हमारे मन को ठीक रखने में भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमें एलोपैथी, होम्योपैथी अनेक तरह की दवाओं का प्रयोग करने के साथ-साथ डॉक्टरों की सिंपैथी की जरूरत है, चिकित्सकों को अपने कर्तव्य का निर्वहन एवं बीमार मरीज के इलाज में अपने अनुभव को पूरी

तरह से उपयोग करना चाहिए। सिर्फ इयूटी या औपचारिकता नहीं निभाना चाहिए। क्योंकि पीड़ित मरीज को भगवान के बाद चिकित्सक पर ही सबसे बड़ा भरोसा होता है। कार्यक्रम में डॉक्टर अभिषेक जैन (सपत्नी) मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी देवेन्द्रनगर एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

## नये कानून को लेकर थाना सलेहा में आम लोगों को थाना प्रभारी द्वारा दी गई जानकारी

पन्ना। 1 जुलाई से पूरे देश में केन्द्र सरकार द्वारा कानून की धाराओं में बदलाव किया गया है। जिसको लेकर सभी थानों में बैठके आयोजित कर भारत सरकार द्वारा लाये गये कानून के संबंध में जानकारी दी गई। इसी कड़ी में जिले के सलेहा थाना परिषद में बैठक का आयोजन थाना प्रभारी सरिता तिवारी द्वारा किया गया तथा आम लोगों को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं से अवगत कराते हुए लोगों को बताया गया। इस अवसर पर थाना क्षेत्र के लोगों को बुलाया गया

तथा पम्पलेट तथा अन्य माध्यमों से कानून की धाराओं में हुए बदलाव से अवगत कराया। इस दौरान अनेक लोग उपस्थित रहे जिसमें मुख्य रूप से वन विभाग से रेजर, डिप्टी रेजर, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष मदन पांडेय, मंडल अध्यक्ष हरेंद्र त्रिपाठी, रामशिरोमणि मिश्रा, शिवनारायण पांडेय, छोटू जैन, सुनील मिश्रा, सरपंच ग्राम पंचायत भाटिया, सरपंच ग्राम पंचायत हरीरा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधी, गणमान्य नागरिक, व्यापारी वर्ग उपस्थित रहा।

## बृहस्पति कुंड पर बनेगा मध्य प्रदेश का पहला 'ग्लास ब्रिज'

पन्ना। पन्ना जिले में स्थित बृहस्पति कुंड जलप्रपात पर प्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज बने जा रहा है। यह देश का तीसरा ग्लास ब्रिज कहलाएगा। जिला प्रशासन ने यहाँ पर ग्लास ब्रिज बनाने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा था, जिसकी मंजूरी पूर्व में ही हो चुकी थी। अब टेण्डर भी जारी हो गया है। ग्लास ब्रिज बनने से पर्यटक करीब से बृहस्पति कुंड को देख सकेंगे, प्राप्त जानकारी के अनुसार, बृहस्पति कुंड जलप्रपात पर बने वाला भारत का तीसरा ग्लास ब्रिज कांच से बनाया जाएगा।

## सांसद आदर्श ग्राम पंचायत जमुनहाई में व्यापक भ्रष्टाचार

सांसद निधि, विधायक निधि, मनरेगा, पंच परमेश्वर की राशि में भारी गोलमाल

पन्ना। ग्राम पंचायतों में वर्तमान समय में निर्माण कार्य तथा विकास कार्यों में व्यापक स्तर पर फर्जीबाड़ी की खबरें सामने आ रही हैं। सबसे अधिक फर्जीबाड़ी पन्ना जनपद पंचायत अंतर्गत गाम पंचायतों में चल रहा है। जहाँ पर पुराने निर्माण कार्यों को नया दर्शाकर सरपंच, सचिव, उपयंत्रियों द्वारा मिलकर शासकीय राशि में फर्जीबाड़ी तथा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सबसे अधिक भ्रष्टाचार मनरेगा योजना सहित सांसद निधि, विधायक निधि तथा पंच परमेश्वर से मिलने वाली राशि में भी किया जा रहा है। जहाँ एक ओर वर्तमान समय में मनरेगा योजना अंतर्गत पन्द्रह लाख की लागत से बनाई जा रही फसल सुरक्षा दीवारों जो पुरानी बनी हुई हैं। उन्हे नया दर्शाकर भारी फर्जीबाड़ी किया जा रहा है। जिसमें पुरानी फसल सुरक्षा दीवारों को नया दर्शाकर राशि आहरित की जा रही है। इसी प्रकार का मामला पन्ना जनपद पंचायत अंतर्गत

ग्राम पंचायत जमुनहाई का प्रकाश में आया है। जहाँ पर जमुनहाई ग्राम पंचायत के ग्राम राजपुर में पुरानी फसल सुरक्षा दीवार को नया दर्शाकर लगातार मजदूरी एवं मटेरियल की राशि आहरित की गई है। पन्द्रह लाख की लागत से बने वाली उक्त फसल सुरक्षा दीवार बम्बुशकल लाख दो लाख की राशि खर्च करके पूरी दर्शा दी जा रही है। पूर्व में किसानों द्वारा अपने खेतों में जानवरों से बचाने के लिए खकरो बनाई गई थी। उन्ही पुरानी खकरी को नया दर्शाकर राशि आहरित की गई है। ग्राम राजपुर में उक्त फसल सुरक्षा दीवार रघु गौड़ के खेत से गुरुवा गौड़ के खेत तक बनाई जा रही है। जो दर्शाया गया है जबकी नब्बे प्रतिशत उक्त फसल सुरक्षा दीवार पूर्व से ही स्वयं किसानों द्वारा बनाई गई है। पंचायत द्वारा सिर्फ थोड़ी पत्थर लगाकर ऊंचाई की गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह फसल सुरक्षा दीवार पूर्व से ही बनी हुई है। कुछ स्थानों पर सुरक्ष

करके बनाया गया है। इस प्रकार से भारी फर्जीबाड़ी किया जा रहा है। ग्राम पंचायत जमुनहाई में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार एवं अनिर्मितता की जा रही है। ग्राम पंचायत में अहिलेश सरपंच हैं लेकिन पंचायत का संचालन सरपंच पति रवी डे द्वारा किया जा रहा है तथा उक्त ग्राम पंचायत जनपद पंचायत में पच्चीस वर्ष से पदस्थ उपयंत्रि संजोय जैन के सेक्टर में आती है। उपयंत्रि द्वारा ही इस प्रकार के फर्जीबाड़ी लगातार किये जा रहे हैं। इसके अलावा सांसद अहिलेश ग्राम जमुनहाई हैं जिसको सांसद वीडी शर्मा ने गोद लिया था तथा सांसद निधि से भी लाखों रूपये की राशि ग्राम पंचायत को विभिन्न कार्यों के लिए दी गई थी। उक्त कार्यों में भी भारी गोल माल करते हुए राशि को ठिकाने लगाया गया है तथा विधायक निधि, एवं पंच परमेश्वर योजना के तहत दी गई राशि में भी भारी फर्जीबाड़ी किया गया है। उक्त ग्राम पंचायत के अंतर्गत राजपुर, मठली, सहित ग्राम प्राप्त आते हैं। जिनमें अधिकांश गरीब तथा आदिवासी वर्ग रहते हैं। सरपंच द्वारा उनके प्रधानमंत्री आवास एवं अन्य छोटे छोटे कार्य भी नही किये जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई वर्षों से रवी डे एवं इनके परिवार के सदस्य सरपंच रहे हैं जिनके द्वारा भारी फर्जीबाड़ी किया गया है। इसी प्रकार उपयंत्रि तथा सचिव का भी हाल है।

**इनका कहना है**  
संबंधित मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, मामले को जांच कराई जायेगी तथा दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कराई जायेगी।  
अशोक चतुर्वेदी अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना  
यह फसल सुरक्षा दीवार पूर्व से बनी हुई थी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त फसल सुरक्षा दीवार को थोड़ा ऊपर किया गया है बाँकी वह पुरानी है।  
सुमी आदिवासी निवासी राजपुर

## यातायात पुलिस द्वारा ऑटो, ई- रिक्शा के विरुद्ध संचालित किया गया विशेष अभियान

पन्ना। पुलिस अधीक्षक पन्ना साई कृष्णा एस थोटा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती आरती सिंह व अनुविभागीय पुलिस अधिकारी एस.पी.सिंह बघेल के निर्देशानुसार ऑटो, ई- रिक्शा चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान संचालित किया गया। जिसमें थाना प्रभारी यातायात निरीक्षक नीलम लक्षकार व यातायात स्टाफ द्वारा लिस्सु विद्यालय पर वाहन चैकिंग के दौरान ऑटो रिक्शा ई-रिक्शा चालकों द्वारा स्कूली बच्चों को छमता से अधिक बैठाये पाये जाने पर रोककर उनके बीमा, फिटनेस, परमिट सहित अन्य सभी जरूरी

कागजात चैक किये गये। जिन वाहनों में छमता से अधिक स्कूली बच्चे पाये जाने पर विभिन्न धाराओं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानों कार्यवाही की गयी। सम्पूर्ण अभियान के दौरान कुल 16 वाहन चालकों विरुद्ध चालानों कार्यवाही कर 8 हजार एक सौ रूपये समन शूल्क बसुल किया गया। थाना प्रभारी यातायात के द्वारा ऑटो मालिकों/चालकों से अपील है की गयी कि, वाहन के सम्पूर्ण कागजात जैसे की ड्रायविंग लाइसेंस, फिटनेस, परमिट, बीमा आदि सभी जरूरी दस्तावेज आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।

## चन्द्रभान सेन संभागीय प्रभारी बनें

पन्ना। जिले के पत्रकार चन्द्रभान सेन को वन्दे भारत न्यूज चैनल द्वारा सागर संभाग का संभागीय ब्यूरो चीफ प्रभारी बनाया गया है। उनके अधिकार क्षेत्र में सभी संभाग के पांचों जिला रहेंगे। श्री सेन को उक्त दायित्व दिये जाने पर साथी पत्रकारों, शुभ चिंतकों, सट मित्रों ने बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

**ऑल इंडिया लीनेस क्लब डिस्ट्रिक्ट सी एम वन संपदा के अंतर्गत 2 जुलाई को एक नए क्लब लीनेस क्लब कामाख्या सीधी का गठन किया गया। जिसमें डॉ. बीना मिश्रा को अध्यक्ष घोषित किया गया।**



## मध्यप्रदेश के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगा बजट : उप-मुख्यमंत्री

प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित बजट के लिए व्यक्त किया आभार

रीवा। उप-मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल व दक्ष नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर विस्तार हो रहा है। भारत आज विश्व 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार अपना योगदान सुनिश्चित कर रही है। यह प्रसन्नता का विषय है कि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 16 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। यह बजट मध्यप्रदेश के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगा विकास की गति को तेज करेगा। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सर्व जनहिताय, विकासोन्मुख बजट के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उप-मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा का आभार व्यक्त किया है।

कहा कि कुशल वित्तीय प्रबंधन से प्रदेश के समग्र विकास हेतु हर क्षेत्र में संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। शिक्षा व स्वास्थ्य, युवा और महिला सशक्तिकरण, सामाजिक उत्थान, अधोसंरचनाओं का विस्तार, रोजगार-स्वरोजगार के अवसर, औद्योगिक विकास आदि के साथ-साथ पर्यावरण, संस्कृति के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधनों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा है कि बजट, प्रदेश को विकसित बनाने के प्रयासों को और अधिक सफल व परिणामजनक बनाएगा। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सशक्त विकसित प्रदेश के लिए नागरिकों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। इसे प्राथमिकता देते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 हेतु रूपये 21 हजार 444 करोड़ का प्रावधान किया है, जो कि वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 34



प्रतिशत अधिक है। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश को निरंतर बढ़ा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए इण्डियन पब्लिक हेल्थ स्टैण्डर्ड के मापदंडों को लागू किया जा रहा है। सरकार ने 46 हजार से अधिक नवीन पदों का सृजन किया गया है। आगामी 2 वर्षों में इन पदों की पूर्ति के प्रयास हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक पहुंच हो, इसलिए संस्थागत व्यवस्था को भी मजबूत बनाया गया है।

उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि चिकित्सकीय सेवाओं के प्रदाय के लिए चिकित्सकीय मैनपावर की पर्याप्त उपलब्धता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। प्रदेश में वर्ष 2003 में मात्र 5 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय ही संचालित थे। सरकार के अथक प्रयासों से वर्तमान में 14 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं। वर्ष 2024-25 में 3 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय -मंदसौर, नीमच एवं सिवनी में संचालित हो जायेंगे। इसके पश्चात आगामी 2 वर्षों में 8 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित करने हेतु भी हमारी सरकार प्रयासरत है। नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन के उपरांत नवीन सीटों की संख्या स्नातक स्तर पर 3 हजार 605

एवं स्नातकोत्तर स्तर पर एक हजार 507 हो जायेंगी। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सभी नागरिकों तक बेहतर चिकित्सा सुविधा के दृष्टिगत आयुष्मान भारत योजना का दायरा और भी अधिक विस्तृत किया है। अब तक लगभग एक करोड़ 8 लाख परिवारों के 4 करोड़ एक लाख सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान हितग्राहियों के लिये नवीन हेल्थ बेनिफिट पैकेज-2022 लागू किया गया है, जिसमें पूर्व की एक हजार 670 चिकित्सा प्रक्रियाओं को विस्तारित करते हुये अब एक हजार 952 प्रक्रियाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभांशित किया जा रहा है। राज्य में अब एक हजार से भी अधिक चिकित्सालय योजना के अंतर्गत संबद्ध हैं। आयुष्मान भारत योजना के लिए रूपये एक हजार 381 करोड़ का प्रावधान है, जो गत

वर्ष की तुलना में 45 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में उपचार के दौरान दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाने पर पार्थिव शरीर, परिजनों को सम्मानपूर्वक सौंप कर, घर तक पहुंचाने के लिये मध्यप्रदेश शांति वाहन सेवा प्रावधानित है। गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उचित समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने हेतु पी.एम. श्री एअर एम्बुलेंस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। राज्य के नागरिकों को निःशुल्क जाँच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निजी-भागीदारी के माध्यम से वेत लीज मॉडल अंतर्गत जिला चिकित्सालयों में 132 प्रकार की, तथा हब एण्ड स्पोक मॉडल के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 45 प्रकार की जाँच सुविधायें उपलब्ध करायी गई हैं। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट और सहजता से उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार कृत-संकल्पित है।

## मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की किस्त 5 जुलाई को होगी जारी

रीवा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 5 जुलाई को लाड़ली बहना योजना की माह जुलाई की राशि सिंगल क्लिक से जारी करेंगे। मुख्यमंत्री टीकमगढ़ जिले के ग्राम छिपरी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से राशि जारी करेंगे। इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री उज्वला योजना से लाभान्वित लाड़ली बहना योजना के हितग्राहियों को गैस रिफिल की

अनुदान राशि तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हितग्राहियों को राशि सिंगल क्लिक से जारी करेंगे। इस कार्यक्रम का वेबकास्ट के माध्यम से पूरे प्रदेश में सजीव प्रसारण किया जाएगा। सभी कमिश्नर, कलेक्टर तथा अन्य संबंधित अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

## जन्म-मृत्यु पंजीयन के संबंध में प्रशिक्षण 5 जुलाई को

रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार मऊगंज में जन्म-मृत्यु पंजीयन के संबंध में प्रशिक्षण दिया जायेगा। अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार एवं कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव ने जिले के चिकित्सा विभाग, सीएमओ, सीईओ एवं प्रबंधक निजी स्वास्थ्य संस्थाएँ ( डाटा इंटी

आपरेटर) को दोपहर 12 बजे से आयोजित प्रशिक्षण में उपस्थित के निर्देश दिये हैं। जिला रजिस्ट्रार एवं संयुक्त संचालक से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य को सुगम बनाने के उद्देश्य से पोर्टल लांच किया गया है।

## जिला लोकल लेबल कमेटी की बैठक संपन्न

बताया गया कि राष्ट्रीय न्यास निरामय योजनाअंतर्गत 150 हितग्राहियों का बीमा कराया गया है। इस अवसर पर निर्देश दिये गये कि लोकल गार्जियन के आवेदन पूर्ण परीक्षणोपरत ही अनुमोदित कराये जायें। बैठक में संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अंनिल दुबे, डॉ. प्रभाकर चतुर्वेदी, ए.के. खान, के.पी. गुप्ता, विनोद श्रीवास्तव, संतोष अवधिया, शशिधरमणि त्रिपाठी, दिवाकर सिंह तथा राजकी पाण्डेय उपस्थित रहे।

रीवा। राष्ट्रीय न्यास लोकल लेबल कमेटी की बैठक अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में विधिक संरक्षकता के आवेदनों पर विचार एवं निष्पत्ति के दौरान कुल प्राप्त 12 आवेदनों में से 11 आवेदनों का अनुमोदन किया गया। कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में

## प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन 10 जुलाई को

रीवा। शासकीय संभागीय आईटीआई रीवा में 10 जुलाई को प्रातः 10 बजे से प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया है। आईटीआई एवं 10वीं परीक्षा में 60 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण युवक/युवतियाँ माइलान लेबोरेटरीज पीथमपुर इंदौर में भर्ती हेतु शामिल हो सकते हैं। प्राचार्य ने बताया कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, टर्नर, वेंडर, एमएमवी के प्रशिक्षार्थी जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष के बीच हो दस्तावेज व पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफस के साथ नियत समय पर उपस्थित हो सकते हैं।

## नगरीय निकायों की मतदाता सूची के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैनात

रीवा। नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की जा रही है। इसके लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैनात किए हैं। नगर निगम रीवा के लिए एसडीएम हुजूर वैशाली जैन को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है। नगर निगम में वार्ड क्रमांक एक से वार्ड क्रमांक 9 तक के लिए संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, वार्ड क्रमांक 10 से 18 के लिए नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, वार्ड क्रमांक 19 से वार्ड क्रमांक 27 के

लिए नायब तहसीलदार अरुण यादव, वार्ड क्रमांक 28 से वार्ड क्रमांक 36 के लिए अधीक्षक भूअभिलेख महेन्द्र श्रीवास्तव तथा वार्ड क्रमांक 37 से वार्ड क्रमांक 45 के लिए तहसीलदार हुजूर शिवशंकर शुक्ला को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है। नगर पंचायत गोविंदगढ़ के लिए तहसीलदार हुजूर शिवशंकर शुक्ला को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा नायब तहसीलदार अरुण यादव को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है। नगर पंचायत सिरमौर अरुण यादव को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा एएसएलआर मनोज शुक्ला को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है। नगर पंचायत सिरमौर के लिए तहसीलदार अरुण यादव को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

तथा प्रभारी नायब तहसीलदार रमाकांत तिवारी एवं प्रभारी नायब तहसीलदार दिलीप सिंह को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है। नगर पंचायत सेमरिया के लिए तहसीलदार आँचल अग्रहरी को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा नायब तहसीलदार अर्जुन बेलवंशी को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है। नगर पंचायत सिरमौर अरुण यादव को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा एएसएलआर मनोज शुक्ला को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है। नगर पंचायत सिरमौर के लिए तहसीलदार अरुण यादव को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

नायब तहसीलदार भगवानदास रैदास को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा एएसएलआर वीरेन्द्र द्विवेदी को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है। नगर पंचायत डभौरा के लिए प्रभारी तहसीलदार राजेन्द्र शुक्ला को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा प्रभारी नायब तहसीलदार राजकुमार टांडिया एवं नायब तहसीलदार राजेश शुक्ला को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है। इन्हें मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के प्रावधानों तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

## नगरीय निकायों की मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम तय

रीवा। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निगम तथा अन्य नगरीय निकायों में फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए 4 जुलाई को संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी दिन सभी आयुक्त नगर निगम तथा मुख्य नगर पालिका

अधिकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 6 जुलाई तक प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करके उसके अनुरूप कंट्रोल टेबल में संशोधन करेंगे। कंट्रोल टेबल का 10 जुलाई तक सत्यापन करके डिजिटल हस्ताक्षर किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

नगरीय निकाय के कार्यालयों, विभिन्न वार्डों तथा अन्य विहित स्थानों पर 19 जुलाई को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन करेंगे। मतदाता सूची के प्रारूप की प्रतियाँ 22 जुलाई तक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएंगी तथा स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। मतदाता सूची के संबंध में दावे एवं आपत्तियाँ दो अगस्त को दोपहर बाद

3 बजे तक प्राप्त की जाएंगी। इनका निराकरण 9 अगस्त तक किया जाएगा। निराकृत दावे-आपत्तियों की ऑनलाइन जानकारी 27 अगस्त तक भरी जाएगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावे-आपत्तियों को लिस्ट 29 अगस्त तक तैयार करके उसे सुधार के लिए 30 अगस्त को वेण्डर को उपलब्ध कराएंगे। अंतिम मतदाता सूची दो सितम्बर तक तैयार कर ली जाएगी।

इसे चार सितम्बर तक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। वेण्डर संशोधित अंतिम मतदाता सूची को मुद्रित करके उसे 10 सितम्बर तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। फोटो युक्त मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन सभी वार्डों तथा अन्य विहित स्थानों पर 12 सितम्बर 2024 को किया जाएगा।

## लीनेस क्लब कामाख्या का गठन डॉ. बीना मिश्रा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष घोषित किया

रीवा। ऑल इंडिया लीनेस क्लब डिस्ट्रिक्ट सी एम वन संपदा के अंतर्गत 2 जुलाई को एक नए क्लब लीनेस क्लब कामाख्या सीधी का गठन किया गया। इस अवसर पर हमारी पास्ट माल्टल प्रेसिडेंट, लीनेस अंजू कटार, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लीनेस दीपा घई व एरिया 2 एरिया ऑफिसर लीनेस सोमा अग्रवाल की उपस्थिति रही। सभी सदस्यों को लीनेस की शपथ लीनेस अंजू कटार जी के द्वारा दिलाई गई। लीनेस दीपा घई जी द्वारा सभी को क्लब

हमने एक बड़े उद्देश्य की ओर काम करने के बारे में बात की। ज़रूरतमंदों और गरीबों को मदद करना, युवा लड़कियों और महिलाओं को पेरियड्स के बारे में शिक्षित करना, आवश्यकता के समय में एक-दूसरे को बाधाओं से उबरने में मदद करना। एकजुट होकर एक मजबूत समाज का निर्माण करना। हम सप्ताह और समाज में महिलाओं की खुशी पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएँ शायद ही कभी खुद का उत्सव मनाती हैं।

## परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के लिये 10 जुलाई तक करें आवेदन

रीवा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, बीमा तथा कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित चयन परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। परीक्षा पूर्व यह प्रशिक्षण ज्ञानोदय विद्यालय केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-एक के पास निःशुल्क दिया जायेगा। प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पात्र आवेदक 10 जुलाई तक कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक से आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष तथा परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपए कम होना आवश्यक है। आवेदक को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा में 55 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यदि आवेदकों की संख्या अधिक हुई तो अंकों के आधार पर सूची

तैयार कर अधिकतम अंकों से क्रमशः चयन किया जाएगा। इस संबंध में संस्था के प्राचार्य ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए चयन होने के बाद विद्यार्थी को पाँच सौ रुपए की सुरक्षा निधि तथा अनुबंध जमा करना आवश्यक होगा। सुरक्षा निधि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वापस की जाएगी। मध्यप्रदेश राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रशिक्षण की अवधि 12 माह की होगी। बैंकिंग, रेलवे, बीमा, एसएससी एवं कर्मचारी चयन मण्डल की परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण अधिकतम 6 माह का होगा। जिन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रवेश परीक्षा की अनिवार्यता है उनकी आवेदन के साथ ऑनलाइन पंजीयन का विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के संबंध में अन्य विवरण टेलीफोन नम्बर 07662-299221 पर संपर्क करके प्राप्त किया जा सकता है।

## सुरक्षा गार्ड भर्ती के लिए जनपद स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन

रीवा। एसआईएस द्वारा जिले के सभी जनपद मुख्यालय में सुरक्षा गार्ड भर्ती के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा सुपरवाइजर एवं सुरक्षा अधिकारी के पद हेतु इच्छुक बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण के उपरांत संस्था द्वारा स्थाई रोजगार से जोड़ा जायेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. सौरभ सोनवणे ने बताया कि गंगेव में 7 जुलाई को, हनुमान में 10 जुलाई को, जवा में 11 जुलाई को, मऊगंज में 12 जुलाई को, नईगढ़ी में 15 जुलाई को, रायपुर कर्चुलियान में 16 जुलाई को, रीवा में 17 जुलाई को, सिरमौर में 18 जुलाई को तथा त्योंथर में 19 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। यह मेले प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होंगे। रोजगार मेले में 19 वर्ष से 40 वर्ष आयु के 10वीं कक्षा पास/फेल 167.5 से.मीटर ऊंचाई के युवा शामिल हो सकते। संस्था द्वारा 350 रूपये पंजीयन शुल्क जमा करने के बाद चयनित होने के पश्चात प्रशिक्षण का व्यय स्वयं करना होगा।

## मेडिकल विंग भोपाल जोन के द्वारा चिकित्सकों का सम्मान किया गया

चिकित्सकों ने मानवता की सेवा में अपना पूर्ण योगदान देने का किया दृढ़ संकल्प

रीवा। विभिन्न क्षेत्र के चिकित्सकों का सम्मान मेडिकल विंग भोपाल जोन के द्वारा ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय रीवा में किया गया इस अवसर पर चिकित्सकों ने यह शुभ संकल्प लिया कि वह पूर्ण निष्ठा व लगन से मानवता की सेवा में तत्पर रहेंगे। साथ ही पूर्ण सच्चाई व ईमानदारी से प्रत्येक मरीज की सेवा करते उनके प्रति सच्ची हमदर्दी और सहन भूति रखकर वह पुनीत कार्य करते रहेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं ईश्वर परमपिता से उन्हें प्राप्त हुई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजकुमार आचार्य जी ने चिकित्सकों का सम्मान करते हुए कहा कि चिकित्सक सही अर्थों में मानवता को दुर्बलों से मुक्ति दिलाने

लखटकिया, डॉक्टर पंकज चौधरी, डॉ. रामाभीलास दुबे, डॉ. केपी गुप्ता, डॉ. बाय एस बघेल, डॉ. अमित सिन्हा, डॉ. प्रियंका परोहा, डॉक्टर दीपक द्विवेदी, डॉक्टर अनामिका द्विवेदी, डॉक्टर शुभम त्रिपाठी, डॉ. के.पी. गुप्ता, आरबी मिश्रा, डॉ. पंत,

आरबी मिश्रा, डॉ. पुष्पा पांडे, डॉक्टर पुष्पा शुक्ला, डॉक्टर मुजीब खान, डॉ. भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर पंत, डॉक्टर प्रवीण पटेल, डॉक्टर रिचा सिंह, डॉ. ज्योति पांडे, डॉ. सिद्धार्थ शुक्ला, डॉ. केबी गौतम सहित 100 से अधिक चिकित्सकों का सम्मानित किया गया। मेडिकल विंग भोपाल जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बीके अर्चना बहन ने सभी चिकित्सकों के राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में राज योगिनी बीके निर्मला दीदी ने सभी चिकित्सकों को निरंतर मानवता की सेवा में तत्पर रहने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन बीके सुभाष भाई एवं बीके दीपक तिवारी ने संयुक्त रूप से बहुत ही सुचारू ढंग से किया।

वाले सच्चे प्रहरी हैं, उनका सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर जिन महत्वपूर्ण चिकित्सकों का सम्मान हुआ उसमें डॉक्टर के.के. परोहा, डॉक्टर सी.बी. शुक्ला, डॉक्टर एच.पी. सिंह, डॉक्टर पी.सी. द्विवेदी, डॉक्टर ज्योति सिंह, डॉक्टर पीके